आन्दोलन को शान्त रीति से चला रहे हैं, यदि उस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो परिस्थिति बड़ी खराब हो जायगी। इसलिए आप लोग यहां से प्रयत्न करें ताकि ऐसा आन्दोलन शुरू न हो और किसानों को जमीन मिल सके।

17.01 hrs.

DISCUSSION RE: REPORTED SALE OF MILITARY MATERIALS BY WEST GERMANY TO PAKISTAN

Mr. Speaker: We will now take up the one hour discussion under rule 193. If hon. Members are brief, we will be able to go round all the parties and a few others also.

Shri Nath Pai (Rajapur): Sir, before you proceed I would like to suggest that though technically the debate is limited to one hour, in view of its paramount importance, the time may be extended. I have already spoken to the Minister of Parliamentary Affairs in the matter. Mr. Speaker, this House does not get enough time to discuss matters of importance. The other House allotted 2½ hours for this. We have been pleading all this session to get a chance to discuss this. Because, this government does not understand the importance of this issue, we want to make an attempt to educate them and, Sir, you should co-operate with us in that effort by extending the time.

Mr. Speaker: Let us, for the present, have one hour discussion. As all of you know, such discussion is always over-flowing. I will give a chance to all parties; one from this side and one from that side and so on.

Shri Ranga (Srikakulam): If you give time that way, Congress members alone will get a major portion of the time.

Mr. Speaker: No, no. I will try to ensure that all parties are given chance. Now, Shri Prakash Vir Shastri.

Shri Amrit Nahata (Barmer): Sir, may I submit.....

Mr. Speaker: Your raising in your seat is not going to help you. I will give you a chance later on.

Shri Amrit Nahata: Sir, this is something more important. This discussion which is being raised under 193 of the Rules . . .

Mr. Speaker: This point ought to have been discussed with me inside my chamber.

Shri Amrit Nahata: Give me a few minutes; I will explain it.

Mr. Speaker: You are taking away the precious time of the House. I will deduct this from your quota of time.

Shri Amrit Nahata: That is not the point.

Mr. Speaker: That is the point.

Shri Amrit Nahata: I am on the question of initiating the debate.

Mr. Speaker: I told you that I will give you a chance.

Shri Amrit Nahata: My point is that Shri Prakash Vir Shastri cannot initiate this debate. It is because rule 193 lays down that any matter of urgent public importance can be raised for a short duration discussion.

Mr. Speaker: I wasted my time in discussing it with you in my Chamber.

Shri Nath Pai: If you have already discussed it with him, why are you allowing it?

Shri Amrit Nahata: All right, Sir; I bow to your judgment.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान का बटवारा भारत और पाकिस्तान के रूप में उस समय के नेताओं की अदूरदर्शिता की नीति का परिणाम था। उन का अपना अनुमान यह था कि शायद रोज-रोज के झगड़े समाप्त हो जायेंगे जो बटवारे के पक्षपाती मुसलमान हैं वे पाकिस्तान चले जायेंगे बाकी जो हिन्दू, मुसलमान और दूसरे लोग हिन्दुस्तान में शान्ति के साथ रहना चाहें वह यहां रह सकेंगे। लेकिन स्थिति उस से उल्टी ही हुई। पहले की अपेक्षा स्थिति और भयंकर होती चली जा रही है। पाकिस्तान जो प्रारम्भ में भारत को सिरदर्द मालूम होता था आज सीने का कांटा बन कर खड़ा हो गया है। कांग्रेस अपनी उस पुरानी ऐतिहासिक भूल का सुधार कर सकेगी, इस संबंध में सन्देह दिखाई देता है, क्योंकि उस के पास आज कोई सरदार पटेल नहीं है। यों भी कांग्रेस भारत के लगभग 60 प्रतिशत भाग से अपना शासन समाप्त कर चुकी है और नहीं कहा जा सकता कि आगे चल कर स्थिति क्या हो? लेकिन जो सब से बड़ा खतरा है वह यह है कि जाते जाते कहीं देश को भी अपने साथ न ले जाये।

श्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन बार बार यह कहते रहे कि चीन से भारत को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, उसी तरह से वर्तमान रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्री हथियारों की इस बिक्री को सामान्य घटना समझ कर उस से मिलती जुलती ही बात बोल रहे हैं। जब कि सीमा पर संघर्ष के बादल धीरे धीरे अपना रंग बदल रहे हैं और नहीं कहा जा सकता कि आगामी शरद ऋतु में वह कौनसा संकट का सन्देश ले कर आ रहे हैं। ऐसे समय में इस घटना को सामान्य समझना स्थिति की उपेक्षा करना होगा। मेरा अपना अनुमान ऐसा है कि सम्भव है चीन इस बार सीधे संघर्ष में न उतरे, लेकिन पाकिस्तान को आगे कर के चीन उसकी कमर पर हाथ रख कर भारत को चोट देने में कोई कसर बाकी नहीं उठा रखेगा। उस का सीधा लक्ष्य है कि पश्चिम में काश्मीर की स्थिति को डगमगाना और पूर्व में पश्चिमी बंगाल की स्थिति को डगमगाकर भारत के पूर्वी भाग को शेष भारत से अलग करना।

जहां तक भारत का संबंध है हमारी असफल विदेश नीति का यह परिणाम है कि नये मित्रों का संग्रह करना तो दूर, हम पुराने मित्रों को भी खोते चले जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान कूटनीतिक क्षेत्र में यहां तक सफल हो चुका है कि अमरीका के अतिरिक्त वह चीन से भी सहयोग प्राप्त कर रहा है और रूस जिसकी मित्रता को खरीदने के लिये हम ने भंयकर से भंयकर संघर्ष मोल लिये आज उस ने भी भारत और पाकिस्तान को एक समान तराजू पर तोलना शुरू कर दिया है। 1965 में पाकिस्तान ने जो कुछ खोया, उस का बहुत बड़ा भाग ताशकन्द से उस ने प्राप्त कर लिया था समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रही सही कसर वह अमरीका, चीन, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, इन देशों से सैनिक सामग्री प्राप्त कर के पूरी कर चुका है। 1965 में पाकिस्तान जहां था, उस से बहुत अधिक आगे जा चुका है। पाकिस्तान ने विमानों, टैंकों और दूसरे रूप में अपनी तमाम आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, इतना ही नहीं अणु अस्त्र प्राप्त करने में भी वह भारत से कहीं आगे जा चुका है। पाछे पाकिस्तान की ओर से भारत के विरोध में जो आन्दोलन चला था कि भारत अणु बम का निर्माण कर रहा है, उसका एक मात्र उद्देश्य यह था कि जिन देशों के पास अणु बम है; विशेष कर अमरीका और चीन जैसे देश, वे पाकिस्तान को अणु अस्त्रों से लैस करें ताकि किसी समय पाकिस्तान पर इस ओर से भी खतरा न हो सके। अमरीका पाकिस्तान में गुप्त रूप से जो बाडबेर हवाई अड्डा बना

रहा है, वह पाकिस्तानी हितों की रक्षा के लिये नहीं है, तो और किस के लिये है ?

ऐसी स्थिति में भारत के रक्षा मंत्री केवल दम्भ के साथ यह कह कर देश को सन्तोष देना चाहें कि हम हर तरह से मुकाबला करने के लिये तैयार हैं, कहां तक ठीक है ? ऐसा होता तो मैं समझता हूं कि आज सदन को, मुझको और आपको किसी प्रकार की कोई चिन्ता न होती लेकिन रक्षा मंत्री का वक्तव्य उसी प्रकार का है जैसे बिल्ली को आता हुआ देखकर कबूतर आंख बन्द कर के बैठ गया था और यह समझने लगा कि संकट टल गया। अध्यक्ष महोदय, 1965 में जब पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर हमला किया था, उसी समय देश के कोने कोने से आवाज उठी थी कि भारत को या तो इस सांप के दांत तोड़ने चाहियें ताकि यह आगे किसी को काट न सके, या उसकी कमर तोड़ी जाय ताकि यह आगे सरक न सके। लेकिन भारत सरकार ने जो भूल 1947 में की थी जब काश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, यानी लड़ाई को आधा बीच में छोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार की भूल 1965 में भी हम ने की कि संघर्ष का सामना तो किया लेकिन लड़ाई को बीच में रोक बैठे। जवाब दिया भी पर आधा ही दिया। आज वही चोट खाया हुआ सांप विदेशी हथियारों का सहारा लेकर हमारी सीमाओं पर फिर फुंकार कर खड़ा हो गया है। 1965 में जो पाकिस्तान की शक्ति थी उस से कहीं अधिक शक्तिशाली आज पाकिस्तान हो गया है। इस समय पाकिस्तान के पास, अध्यक्ष महोदय, 10 डिवीजन अपनी स्थल सेना है। उस 10 डिवीजन स्थल सेना में 8 डिवीजन तो इनफैन्टरी हैं। 1 डिवीजन आरमर्ड कोर है जो अमरीकी टैंकों से लैस है और 1 डिवीजन आरमर्ड कोर चीनी टैंकों से लैस है। 10 डिवीजन स्थल सेना पाकिस्तान के पास इस तरह है।

जहां तक हवाई जहाजों का संबंध है पाकिस्तान की 20,000 के लगभग एयरफोर्स की अपनी स्ट्रैंग्थ पहुंच चुकी है। उस में पाकिस्तान के पास लगभग 33 स्क्वैड्रन हवाई जहाजों की शक्ति है जो भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। चीन के द्वारा जो हवाई जहाज पाकिस्तान को मिले हैं उस में 130 मिग विमान 17 तथा 19 किस्म के हैं तथा इल्यूजन 28, मीडियम रेंज बाम्बर्स किस्म के भी काफी विमान चीन ने दिये हैं। वह भी पाकिस्तान ने चीन से प्राप्त किये हैं। चीन ने केवल हथियार या हवाई जहाज ही नहीं दिये बल्कि 97 विमान भेदी तोपें जहाजों को गिराने वाली भी पाकिस्तान को दी है। इसी प्रकार से पाकिस्तान ने फ्रांस से खुले बाजार से कुछ हवाई जहाज खरीदे हैं जिनमें एफ-86 जेट विमान भी 90 की संख्या में वहां से पाकिस्तान को मिले हैं। योरुप के खुले बाजार से भी उसने उतने ही लगभग जहाज खरीदे हैं। एक स्क्वाडरन एफ-104 सुपर सोनिक स्टार फाइटर भी पाकिस्तान ने खरीद लिये हैं जबकि कैनाडा से लगभग 90 विमान इस प्रकार के पश्चिम जर्मनी से ईरान होकर कनाडा में बने यह एफ86 विमान पाकिस्तान को मिले।

एक गम्भीर चेतावनी देने वाली बात जो पीछे दिल्ली की एक हिन्दी समाचार समिति, समाचार भारती, ने इस देश को दी थी वह यह कि पाकिस्तान के पास मिराज 3 किस्म के मिग विमान भी हैं। यह विमान वह हैं जिनसे इजरायल ने अभी अरब के ऊपर आक्रमण किया था। इस विमान की गति एक घंटे में 1400 मील की है। यह विमान सुपरसोनिक विमानों की तरह उतरने चढ़ने के लिए अधिक स्थान नहीं लेते। यह विमान 2800 फिट के हवाई अड्डे पर उतर भी सकते हैं और उस से उड़ान भी भर सकते हैं। इस विमान की सब से बड़ी विचित्र बात यह है कि हर मिराज 3 के अन्दर

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

और 530 मिजाइल भी लगी हुई हैं। यह आज पाकिस्तान के पास आ चुके हैं। शायद यही कारण था कि जो एयर मार्शल अर्जुन सिंह ने इस बात को कहा था कि पाकिस्तान की वायु सेना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन कर खड़ी हो गयी है। ऐसी स्थिति में इन तमाम चीजों को सामान्य समझ कर छोड़ देना यह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। कैनाडा से और जर्मनी से जो जहाज पाकिस्तान आये और जब सदन में उस पर चिन्ता व्यक्त की गई तो विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान ने अपने जहाज वापिस ले लिये हैं। मरम्मत के लिए वह पाकिस्तान को दिये गये थे। नहीं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान हवाई जहाजों की मरम्मत के मामले में इतना एक्सपर्ट कब से हो गया है?

जो हवाई जहाज दिये गये थे यह जहाज अध्यक्ष महोदय, आज भी पाकिस्तान के संरक्षण में हैं। हो सकता है कि यह जहाज पाकिस्तान की धरती पर न हों लेकिन यह जहाज ईरान के जाईदान हवाई अड्डे पर खड़े हैं। जाईदान ईरान और पाकिस्तान के किनारे पर बसा हुआ है और वह पाकिस्तान और ईरान की सीमा को मिलाता है। अब पाकिस्तान से जाईदान को सीधा सम्पर्क करने के हेतु रेलवे लाइन भी लगभग तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान और ईरान के राजनयिक सम्बन्धों की घनिष्ठता का यह परिचायक है कि पाकिस्तान ने जाईदान तक के लिये रेलवे लाइन बिछाई है। वहां पर वह सारे जहाज खड़े हुए हैं। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं क्या वास्तव में यह जहाज ईरान को वापिस हुए हैं? अभी पीछे कुछ दिन पूर्व जब ईरान के शाह पाकिस्तान का दौरा करने के लिए आये तो ईरान के शाह के सम्मान में पाकिस्तान ने कुछ विमानों का प्रदर्शन किया और उनमें उन्हीं सेबरजेट विमानों का प्रदर्शन किया जो पाकिस्तान को कनाडा और पश्चिमी जर्मनी के मार्फत होते हुए ईरान के द्वारा मिले थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो विशेष बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आश्चर्य यह है कि इन सारी चीजों का रहस्य हम को विदेशी सूत्रों से पहले प्राप्त होता है। पाकिस्तान को भारी मात्रा में पश्चिमी देशों और चीन से जो हथियार मिल रहे हैं उनका पता भी भारत सरकार को विदेशी सैनिक सूत्रों द्वारा ही मिलता है। मैं विदेश मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस गरीब देश का करोड़ों रुपया जो इन राजदूतावासों पर खर्च किया जा रहा है यह हमारे राजदूत अमेरिका, जर्मनी और कनाडा में बैठ कर क्या करते रहते हैं? सारी चीजों का पता हमें दूसरों के माध्यम से चलता है। हमें किसी चीज की जानकारी अपने माध्यम से क्यों नहीं हो पाती।

वायु सेना में वृद्धि के अतिरिक्त भी पाकिस्तान ने अपनी स्थल सेना को टैंकों, तोपों और भारी शस्त्रास्त्रों से युक्त बना लिया है। उसने जो प्रगति की है उस का मैं सदन को कुछ विवरण देना चाहूंगा। चीन में बने हुए 250 टी-59 टैंक और 30 टी-34 टैंक आज पाकिस्तान के पास हैं जो कि उसने चीन से लिये हैं। इसी तरह पश्चिम जर्मनी में बने हुए एम-47 किस्म के नए पैटर्न टैंक भी जहां पाकिस्तान ने नकद भुगतान पर लिये हैं वहां उसे उन से एस-47 टैंक भी 600 की संख्या में मिले हैं। अभी हाल में ही फिर पाकिस्तान सरकार एम 47 और एम 48 किस्म के 200 टैंक और खरीदने की कोशिश कर रही है। कुछ नये सौदे भी पाकिस्तान पश्चिमी जर्मनी से कर रहा है। इससे आपको कुछ अनुमान लगेगा कि पाकिस्तान अपनी शक्ति को कितना बढ़ाता हुआ चला जा रहा है।

अमरीका ने पीछे पाकिस्तान को 150 करोड़ डालर से भी ज्यादा की सैनिक मदद दी थी जब कि इसके मुकाबले में भारत को केवल 6 करोड़ डालर की मदद दी थी।

ऐसी स्थिति में अब आप अनुमान लगाइये कि उसे कितनी अधिक सहायता हमारे मुकाबले मिल रही है ? हमारा देश अमेरिका से पूछना चाहता है कि जब तुम जानते हो कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की गोद में बैठ चुका है, जब तुमको यह पता है कि चीन और पाकिस्तान का गठबन्धन भारत के लिए ही नहीं विश्व की शान्ति के लिये खतरा होता हुआ चला जा रहा है ऐसी स्थिति में अमेरिका पाकिस्तान और भारत को एक तराजू में रख कर तौले व यह हे कि यह जो फ़ालतू पुर्जे हैं या जो सन् 65 में हथियार खराब हो गये थे वह भारत और पाकिस्तान को एक समान रीति नीति के आधार पर दिये जायेंगे यह बात हमारी समझ में नहीं आती । मैं आपके माध्यम से जो बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि आज की स्थिति में चीन और अमेरिका दोनों पाकिस्तान को सहयोग दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के तीन मिलिटरी मिशन रूस का भी पिछले वर्ष दौरा करके आये हैं । रूस की सरकार ने पाकिस्तान को यह कहा है कि जिन शर्तों पर हम भारत को हथियार दे रहे हैं उन्हीं शर्तों पर हम पाकिस्तान को भी हथियार देंगे । कूटनीति के क्षेत्र में पाकिस्तान इतना आगे चला गया है कि रूस के मन में भी पाकिस्तान ने अपने लिए एक सौफ्ट कौरनर बना लिया है । सच्चाई तो यह है कि जब से चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ हुआ है तब से रूस और पाकिस्तान के सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ है । इस समय दुनियां की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म का एक नया समझौता हुआ है । इस समझौते का प्रभाव अगर आपको भारत में देखना हो तो पश्चिमी बंगाल और काश्मीर की घाटी में उस समझौते की छाया देखने को मिलेगी । यह भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए भी एक बहुत गम्भीर चिन्ता की बात है ।

इसके अतिरिक्त पाकिस्तान को दूसरे देशों से खुले बाजारों से सैनिक सामग्री खरीदने के लिए काफी विदेशी मुद्रा भी मिली है । 1965 के भारत पाक संघर्ष के बाद खाली सऊदी अरब ने 10 अरब डालर की विदेशी मुद्रा पाकिस्तान को बिना ब्याज के दी और अब कुछ दिन पूर्व चार सौ करोड़ डालर की और दूसरी विदेशी मुद्रा बतौर ऋण सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया । चीन ने भी हथियारों की खरीद के लिए 1670 लाख डालर का ऋण पाकिस्तान को दिया और भी कई देशों से जिनमें टर्की, ईराक, जोर्डन और सीरिया आदि देश सम्मिलित हैं उनसे पाकिस्तान को अपेक्षित सहयोग मिला है । अब पाकिस्तान को हथियार खरीदने के लिये टर्की ने क्या दिया, ईराक ने क्या दिया, सीरिया ने क्या दिया और जोर्डन ने क्या दिया मैं उन बातों को कह कर सदन का अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहता । लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि स्थल सेना और वायु सेना के अतिरिक्त नौसेना के क्षेत्र में भी पाकिस्तान ने प्रगति की है । चीन की देख रेख में पूर्वी पाकिस्तान में नौसेना प्रशिक्षण चल रहा है । पूर्वी पाकिस्तान में चटगांव और ढाके में चीनी अधिकारियों की देखरेख में नौसेना को चीनी ढंग पर प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चीज है पाकिस्तान के पास वह है अमेरिका से मिली एक गाज़ी नाम की पनडुब्बी जो 1965 से पहले उसके पास थी और जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दे रक्खी थी । लेकिन अब पाकिस्तान ने फ्रांस से दो डाफने पनडुब्बी और खरीद ली हैं । इस तरह से पाकिस्तान की नौसेना को नये तरीकों से और नये सिरे से ट्रेंड किया जा रहा है । ऐसी स्थिति

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

में नौसेना के क्षेत्र में भी पाकिस्तान अब आगे बढ़ता चला जा रहा है । अगर मैं इस सारी बात को संक्षिप्त करके कहूं तो यूं कह सकता हूं कि सैनिक सामग्री की दृष्टि से पाकिस्तान आज भारत की सेना की तुलना में 55 प्रतिशत निकट आ चुका है । पाकिस्तान ने सैनिक सामग्री की दृष्टि से अपने को पर्याप्त समर्थ कर दिया है । इसलिये मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए दो, तीन बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूं । हमें इसका खतरा नहीं कि पाकिस्तान के पास इतने हथियार आ गये हैं या पाकिस्तान हथियारों का गोदाम बन कर खड़ा हो गया है । हमें इससे भी चिन्ता नहीं कि पाकिस्तान एक फौजी छावनी बन कर खड़ा हो गया है । हमें सब से बड़ी चिन्ता इस बात की है कि हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं । 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष में हमारे पास जो शस्त्र थे उसकी तुलना में पाकिस्तान के पास आधुनिकतम शस्त्र थे । पाकिस्तान को दुनिया के उन देशों ने आधुनिकतम हथियार दिये और काफ़ी मात्रा में गोला बारूद भी दिया । लेकिन किसी भी देश ने पाकिस्तान को हिम्मत का पार्सल नहीं भेजा । अगर हथियारों के साथ साथ पाकिस्तान को हिम्मत भी मिल जाती तो शायद पाकिस्तान हथियारों का अच्छा उपयोग कर सकता था । अध्यक्ष महोदय, हमारे पिछले प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाकिस्तान संघर्ष से पहले दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर एक आवाज लगाई थी, कि शान्ति का मुकाबला शान्ति से किया जायेगा, और हथियार का मुकाबला हथियार से किया जायेगा मैं भारत सरकार को यह कहना चाहता हूं कि श्री चागला को याद होगा कि जब पाकिस्तान के संघर्ष के बाद वह यू० एन० ओ० की यात्रा करके आये तो इस सदन में वक्तव्य देते हुए उन्होंने ही यह कहा था कि जब मैं पहले यू० एन० ओ० में कश्मीर के केस को लेकर गया तो मेरी बात को किसी ने ध्यान से नहीं सुना लेकिन जब भारत की विजय के समाचार अमरीकी पत्रों में छपे और इस बार जब मैं कश्मीर के केस को लेकर वहां पर गया तो दुनिया के राष्ट्रों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना । मैं वहां से अनुभव लेकर आया हूं कि आज की दुनिया में जितनी शक्ति की भाषा समझी जाती है उतनी और कोई दूसरी भाषा नहीं समझी जाती है । शान्ति भी शक्ति की छाया में ही सुरक्षित रह सकती है । इस तथ्य को भारत सरकार अपनी आंखों से ओझल न करे और जो देश पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं भारत सरकार उनको स्पष्ट रूप से यह कहे कि हमारे खिलाफ़ हथियार देना हमारे ऊपर युद्ध के लिए पाकिस्तान को उकसायेगा उसे शत्रुतापूर्ण कार्यवाही माना जायेगा । और अगर कोई देश ऐसा करेगा, तो भारत को उसके साथ राजनयिक सम्बन्धों के बारे में फिर से विचार करना पड़ेगा ।

मैं आशा करता हूं कि विदेश मंत्री आज की इस चर्चा को कोई मामूली बहस समझ कर नहीं छोड़ देंगे, बल्कि इसके द्वारा भारत सरकार कुछ गम्भीर निर्णय लेगी ।

श्री अमृत नाहटा (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की सामरिक शक्ति में जो बेहद वृद्धि हो रही है उस से इस सदन का और हमारे देश की सारी जनता का चिन्तित होना अत्यन्त स्वाभाविक है। 1965 में जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया, तो उस वक्त उस के पास पैटन टैंक और सेबर जेट आदि बहुत ही आधुनिकतम हथियार थे । यह सही है कि उस वक्त हम ने उस को पछाड़ा जिस का एक बहुत बड़ा कारण जैसा कि मेरे विद्वान पूर्ववक्ता ने बताया है यह था कि उस के पास हिम्मत नहीं थी । लेकिन उस के अतिरिक्त एक और बात की ओर भी मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं

और वह यह है कि पाकिस्तान के पायलट और आर्मर्ड कोर के सैनिक पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं थे । यह भी एक कारण था कि वे आधुनिकतम हथियारों और औजारों को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके ।

हाल ही में इसराईल ने अरब देशों पर जो हमला किया हमें उस से सबक लेना होगा । पाकिस्तान ने जो हथियार हमारे देश के विरुद्ध इस्तेमाल किये ठीक वही हथियार इसराईल ने अरब देशों के विरुद्ध इस्तेमाल किये । इसराईल की सफलता का रहस्य यह था कि आधुनिक हथियारों से सज्जित होने के साथ साथ उस के अधिकारी और सैनिक आधुनिक युद्ध-कला में प्रशिक्षित और नई समर-नीति से परिचित थे । हमें ज्यादा चिन्ता इस बात की है कि कहीं पाकिस्तान आधुनिक हथियारों को प्राप्त करके और अपनी सेना को आधुनिक युद्ध की कला में प्रशिक्षित कर के हमारे खिलाफ वही सामरिक तरीके न अख्त्यार करे जो कि इसराईल ने अरब देशों के खिलाफ अख्त्यार किये थे । ईश्वर ऐसा न करे, लेकिन हमें इस सम्भावना को दृष्टि में रख कर सजग और सचेत रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए पुरी तैयारी करनी चाहिए ।

लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें न हिन्दुस्तान की जनता का हित है और न पाकिस्तान की जनता का हित है कि दोनों देशों में युद्ध हो । हमें यह अनुभव है कि थोड़े दिनों की पिछली लड़ाई के बाद हमारी स्थिति कितनी विषम हो गई है । इसी प्रकार यह पाकिस्तान की जनता के हित में भी नहीं है कि उस देश की हिन्दुस्तान के साथ लड़ाई हो । लेकिन हमें समझना चाहिए कि वे कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को हिन्दुस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हैं । एक तरफ हम को आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को सामरिक सहायता दे कर हमें मजबूर किया जाता है कि हम भी अपनी सामरिक शक्ति को मजबूत करें और अपना सारा पैसा अपने देश की सुरक्षा में लगा कर अपने आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर दें ।

हमारे आर्थिक विकास को रोकने के लिए, हमारी प्रगति में बाधा डालने के लिए और हमारे प्रजातंत्र को खतरे में डालने के लिए एक तरफ चीन षड्यंत्र कर रहा है और दूसरी तरफ अमरीका, वैस्ट जर्मनी, टर्की और ईरान षड्यंत्र कर रहे हैं । यह एक राजनैतिक षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिससे हमें सजग रहना होगा ।

जहां तक पाकिस्तान को दिये जाने वाले हथियारों का सम्बन्ध है, चाइना ने उस को मिग विमान दिये हैं, टैंक दिये हैं और पैसा दिया है । दूसरी तरफ़ अमरीका ने उस को स्पेयर्ज दिये हैं, टैंक, सेबर जेट्स और एफ०-104 दिये हैं । इसी तरह कैनेडा ने भी . . .

Mr. Speaker: I do not know how far that is correct. The figures have been given already by Shri Prakash Vir Shastri.

Shri Amrit Nahata: I am drawing a conclusion different from what Shri Prakash Vir Shastri has drawn.

मेरे विचार से श्री प्रकाशवीर शास्त्री का दृष्टिकोण गलत है । वह अपने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करना चाहते हैं जबकि हम यह मानते हैं कि जहां एक ओर हमें अपने देश की रक्षा के लिए तैयारी करनी है, वहां हमें यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम ताशकंद समझौते के हक़ में हैं । इस सरकार ने ताशकंद समझौते का उल्लंघन नहीं किया है और अगर पाकिस्तान बेशर्मी से ताशंकद समझौते का उल्लंघन कर रहा है तो इस का कारण यह है कि वह कुछ विदेशी ताकतों

[श्री अमृत नाहाटा]

के हाथ में कठपुतली बन कर काम कर रहा है। जो विदेशी ताकतें इसराईल को अरब देशों के खिलाफ़ इस्तेमाल करती हैं वही ताकतें पाकिस्तान को हिन्दुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि यह देश एशिया में स्वतंत्रता का, प्रजातंत्र का और प्रगति का प्रतीक है। इस लिए इस देश के लिए कठिनाइयां पैदा करने का जो षड्यंत्र है उस के प्रति हमें सजग हो जाना चाहिए।

हमें यह घोषणा करनी चाहिए कि जो ताकतें इस प्रकार पाकिस्तान को हमारे विरुद्ध इस्तेमाल कर रही हैं, वे हमारे देश के प्रति अमित्रतापूर्ण व्यवहार कर रही हैं। इस के साथ ही हमें इसराईल के युद्ध के तरीकों से सबक लेना होगा और उन को ध्यान में रखते हुए अपनी सामरिक और सुरक्षा की तैयारियों को मजबूत बनाना होगा। इस वक्त हम काम्प्लेसेंट नहीं कर सकते। अगर कच्छ ट्रिब्यूनल का फैसला पाकिस्तान के हक में नहीं होता है, तो बहुत मुमकिन है कि वह गड़बड़ी करे। जब पाकिस्तान ने कच्छ पर हमला किया था, तो उस से कुछ दिन पहले अयूब साहब ने यह वक्तव्य दिया था कि हम हिन्दुस्तान के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। आज भी अयूब साहब ने वैसा ही वक्तव्य दिया है। हमारे लिए यह एक चेतावनी की घंटी है। जब अयूब साहब हिन्दुस्तान के साथ दोस्ती रखने की बात करते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि दाल में कुछ काला है और वह दुनिया को धोखे में डालना चाहते हैं। इस लिए यह आवश्यक है कि हमें इस खतरे के प्रति सावधान रह कर अपनी सुरक्षा की तैयारियों को मजबूत बनाना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश के सामने आन्तरिक और बाहरी बहुत से संकट हैं। आन्तरिक संकटों का मुकाबला हम कर सकते हैं, यदि हम बाहरी संकटों का मुकबला करने में समर्थ हों। दुर्भाग्य से आज बाहरी संकट बहुत भयानक रूप धारण करते जा रहे हैं। भारत की सुरक्षा की समस्या अन्य सब समस्याओं से भयानक और गम्भीर होती जा रही है।

पाकिस्तान हमारा शत्रु है और चीन भी हमारा शत्रु है और इन दोनों का गठजोड़ है। हमें इन दोनों देशों को अपना शत्रु मान कर अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध करना होगा। किसी देश की सुरक्षा के चार आधार होते हैं : जनबल (मैनपावर), मनोबल (मोराल), औद्योगिक बल (इंडस्ट्रियल पावर) और शस्त्र बल (मिलिटरी पावर)। किसी देश की सुरक्षा के ये चार मूल आधार होते हैं। इन चारों सतूनों पर छत पड़ती है विदेश नीति की, विदेश नीति की सहायता से ही मुल्क की सुरक्षा होती है। इसलिए सुरक्षा और विदेश नीति का गहरा सम्बन्ध माना जाता है।

दुर्भाग्य से हमारी सुरक्षा नीति ग़लत रही है और हमारी विदेश नीति की छत उस पर नहीं है। परिणाम यह है कि यद्यपि हमारा देश पाकिस्तान से तीन गुना बड़ा है और 1947 में उसकी सैनिक शक्ति पाकिस्तान से तीन चार गुना थी, लेकिन इन बीस वर्षों के बाद हालत यह है कि हम अपना सैनिक संतुलन खो चुके हैं। चाहिए तो यह था कि हमारा मिलटरी बैलेंस, हमारा सामरिक संतुलन होता, चीन और पाकिस्तान दोनों की शक्ति को देख कर, लेकिन चीन तो दूर रहा—उस की शक्ति तो बहुत अधिक है—, हम पाकिस्तान के साथ भी अपना बैलेंस आफ़ पावर बना कर नहीं रख सके।

पाकिस्तान की सैनिक शक्ति दिनों-दिन बढ़ती जा रही है और इसी का परिणाम है कि पाकिस्तान हमें आंखें दिखाता है ।

अभी तीन दिन हुए कि सुरक्षा मंत्री ने एक वक्तव्य में बताया था कि हमारे देश की कितनी भूमि दूसरे लोग दबाए बैठे हैं । वह स्टेटमेंट पढ़ने से शर्म आती है । चीन दबाए बैठा है हमारा पद्रंह हजार वर्ग-मील का इलाका । पाकिस्तान काश्मीर में हमारा चालीस हजार वर्ग-मील क्षेत्र दबाए बैठा है । इस के अतरिक्त आसाम, त्रिपुरा, बंगाल और राजस्थान की सीमा पर लगभग सभी सीमाओं पर, पाकिस्तान हमारा इलाका दबाए बैठा है । इतना ही नहीं, उस की आंख और इलाकों पर भी है और उस के लिए वह तैयारी कर रहा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने पाकिस्तान की सैनिक तैयारी के सम्बन्ध में अभी कुछ आंकड़े हमारे सामने रखे हैं । वे आंकड़े ठीक हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति इस से भी ज्यादा भयानक है । आज पाकिस्तान के पास दो सेनायें हैं : एक वैस्ट्रन आर्मी और दूसरी ईस्ट्रर्न आर्मी । उस की वैस्ट्रन आर्मी पश्चिम से आए हुए हथियारों से सज्जित की गई है और ईस्ट पाकिस्तान में स्थित ईस्ट्रर्न आर्मी मुख्यतः चीन से आए हुए हथियारों से लैस की गई है । आज पाकिस्तान इन दो सेनाओं से हमें दोनों ओर से आंतकित कर रहा है और हमारे लिए खतरे का कारण बना हुआ है ।

इतना ही नहीं, जैसा सुरक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है, उस का सम्बन्ध रूस से सुधर रहे हैं और अब रूस लगभग उन्हीं शर्तों पर उस को हथियार देने को तैयार हो रहा है, जिन शर्तों पर वह हम को हथियार दे रहा है । इस स्थिति में हमें यह देखना होगा कि हम किस प्रकार अपनी रक्षा कर सकते हैं । आज हथियारों के बड़े स्रोत हैं ? हथियार मिलते हैं सहायता के रूप में दोस्तों से । दूसरे आते हैं सैनिक संधियों के द्वारा । आज आप के पास चाहे वे न हों लेकिन कल जब आप की लड़ाई हो तो आप के एलाईज के हथियार आप के काम आ सकते हैं । और तीसरे, ओपेन मार्केट है, खुला बाजार, जिस से खरीद सकते हैं । संसार के अन्दर बहुत बड़ा ओपेन मार्केट है हथियारों का । उसे खरीदने के लिए आप के पास हार्ड करेंसी, डालर और पौंड चाहिएं । पाकिस्तान ने पहले बहुत से हथियार प्राप्त किए अमेरिका से और अब चीन से प्राप्त कर रहा है सहायता के रूप में । पाकिस्तान ने एलाईज बनाए हैं, टर्की और ईरान इनके हथियार भी उस के काम में आने वाले हैं । और फिर पाकिस्तान के पास फारेन एक्सचेंज है । उस ने अपनी आर्थिक हालत अच्छी कर ली है । इसके साथ ही उस को बहुत सा डालर मिला है सउदी अरेबिया इत्यादी और देशों से जिस के द्वारा वह ओपेन मार्केट से भी बहुत कुछ माल खरीद रहा है । यह वह स्थिति है जिस से हमें आखें बन्द नहीं करनी चाहिएं । हमें रोज कहा जाता है कि हम भी तैयारी कर रहे हैं । कर रहे होंगे । मगर हमें आप की बात पर विश्सास नहीं । इस देश की जनता को इस सरकार के आश्वासनों पर विश्वास नहीं क्योंकि गत बीस सालों के उसके अनुभव बड़े कटु हैं । सन् 47 में जब हमारी सैनिक शक्ति पाकिस्तान से चौगुनी थी तब पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला किया । हम उसे रोक सकते थे । लेकिन हम ने अपनी फौजों को रोक दिया । नीति हमारी गलत थी । उस के परिणामस्वरूप पाकिस्तान ने काश्मीर की 40 हजार वर्गमील जमीन हड़प ली । इस के बाद कच्छ पर हमला किया । कच्छ का मामला अब विचाराधीन है । उस में पोलिटिकल फैसला होगा

[श्री बलराज मधोक]

फैसला होगा और मुझे डर है कि आधा कच्छ हमारे हाथ से निकल जायेगा फिर 65 में उस ने हमला किया । हमारे जवानों ने मुकाबिला किया और कुछ इलाका पाकिस्तान का हम ने लिया । लेकिन हमने वह ताशकंद के एग्रीमेंट के कारण वापिस कर दिया । यह कीमत थी जो रूस को हमें देनी पड़ी । अगर रूस पर हम निर्भर न होते तो यह कीमत न देनी पड़ती । उसके फलस्वरूप हम ने जो कुछ लिया था वह पाकिस्तान को वापस मिल गया । उस के बाद हम तो ताशकंद की शराब पी रहे हैं, हम तो ताशकंद की वोडका पी रहे हैं और पाकिस्तान जंगी तैयारियां कर रहा है । हमारे विदेश मंत्री जो ताशकंद के राग अलापते रहते हैं और पाकिस्तान जंग की तैयारी करने में लगा है और आज उसकी सैनिक शक्ति आगे से बहुत बढ़ गई है । इसलिए यह संभावना बढ़ रही है कि अगले दो तीन महीनों के अन्दर पाकिस्तान फिर गड़बड़ करेगा उस गड़बड़ का मुकाबिला करने के लिए तैयार करना होगा देश को और तैयार करना होगा अपनी सेना को और उसे सुसज्जित करना होगा उन हथियारों से जो कि शत्रु के पास है । हमारी सेना अच्छी है । मगर जब तक उस के पास बेहतर हथियार नहीं होंगे अच्छे हथियार नहीं होंगे तब तक हम अपना रक्षा नहीं कर सकेंगे । हम तीन तरफ घिरे हुए हैं । हमारा पांच हजार मील का फ्रंटियर आज जल रहा है; उसकी रक्षा बिना नवीनतम और पर्याप्त अस्त्रों के नहीं हो सकेगी इस दृष्टि से मैं चार सुझाव देना चाहता हूं । पहली बात यह है कि हमें अपने देश को हथियारों के मामले में आत्म-निर्भर करना होगा । उस के लिए हम कुछ कर तो रहे हैं । लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है । उसे बहुत तेजी से करना होगा । सर्वोपरि प्राथमिकता देनी होगी देश के अन्दर डिफेंस इंडस्ट्रीज को और डिफेंस प्रोडक्शन को । इस के साथ साथ हमें दुनिया के दूसरे देशों से, भी हथियार लेने होंगे । चाहे जितनी कीमत से लेने पड़ें तो भी उन्हें लेना होगा । उस के लिए पेट पर पट्टी बांधनी पड़े तो पेट पर पट्टी बांध कर भी लें । तीसरे, हमें अपनी विदेश नीति को सुरक्षा नीति के अनुसार ढालना होगा । विदेश नीति और सुरक्षा नीति के बीच सामंजस्य पैदा करना होगा । उनमें तालमेल लाना होगा । हमें ऐसे साथी बनाने होंगे जो आपत्काल में हमारी सहायता कर सकें । और चौथे हमें दुनिया को बताना होगा कि जो पाकिस्तान का साथ देता है वह भारत का शत्रु है । यह सोचना कि दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत है हमारी जरूरत नहीं है, गलत है हमारी भी दुनिया को जरूरत है । मगर हम दुनिया से उचित भाषा में बोलना सीखें । हमें स्पष्ट भाषा में सभी मुल्कों से चाहे वह सऊदी अरेबिया हो, चाहे, वह ईरान हो, चाहे वह जोर्डन हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे अमरिका हो उसे चाहे रूस हो, स्पष्ट रूप से कहना होगा कि जो पाकिस्तान का साथ देगा, जो पाकिस्तान को हथियार देगा वह हमारे साथ शत्रुता करेगा और भारत उसे बर्दाश्त नहीं करेगा । अगर भारत इस भाषा में बोलेगा तो बहुत से मुल्क जो आज पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं वह देने के पहले हजार बार सोचेंगे कि पाकिस्तान को हथियार देकर भारत जैसे बड़े देश के साथ शत्रुता मोल लें या नहीं । इन चार बातों पर अमल कर के ही हम सुरक्षा के बारे में उचित कदम उठा सकेंगे और जनता को आश्वस्त कर पायेंगे ।

Shrimati Sharda Mukerjee (Ratnagiri): There seems to be a considerable amount of agitation today in the House over what?—over the supply of F-84 Sabres, the same F-84 Sabres which the Gnats did pretty well. last Indo-Pakistan war, and against which the Grants did pretty well. West Germany is supposed to have

supplied M-47 and M-48 tanks. As the Foreign Minister told us, to the best of his knowledge and according to information received, none of these/ has happened. It is true that Pakistan gets equipment from America but it is not new. We have known it for a long time that Pakistan has a military pact with America and she is part of the CENTO and SEATO. Suddenly because there is a newspaper report, we get agitated over it. Regarding this atmosphere of tenseness which is sought to be created over possible hostilities in the next few months, I would like to say that nothing is really gained by creating this sort of tension it is rather like a no-peace-no-war basis—like getting all dressed up for going out with no where to go. If there is any trouble on our frontiers, I think the Army and Air Force are equipped to the extent that it is economically possible for this country to equip them against Pakistan. Secondly, I do not think that Russia or America would risk a large scale conflict in this part of the world. I do not mean to say that we should be complacent or that we should not go ahead with equipping our armed forces as they should be equipped. But what is the cost of equipment to the military forces? What is the cost of one tank? The cost of one tank, leave alone the sophisticated ones, would be Rs. 5 lakhs and even if we were to spend the entire revenue of the whole year we cannot equip the army of the size that we are maintaining today. Therefore, we have to have some self-confidence. Even if a contingency should arise where India and Pakistan are in conflict with each other, the conflict would have a limited span and we are confident of facing that limited conflict as we did in the last 1965 hostilities; we did not do badly in that. I know that we do not have the sophisticated equipment that Pakistan had. What is the price for getting that equipment? Are you willing to go into a military pact with America or with Russia? We know that year after year our military missions have been going to America and Russia? What answer have they come back with? How far has your MIG manufacture gone? What about the ban of the sale of spare parts and its repurcussions in your aircraft industry, in your military equipment industry? What has been the effect? Do you not know what happened after the 1965 hostilities? Do you not know what has happened after our stand on the UAR-Israeli hostilities? This is the price we have to pay and the price is too big. Even Jawaharlal Nehru has said on the floor of this House that if we were to go into a military pact, we would not keep the independence of the country. When there is a large scale conflict, then of course we cannot hang on to non-alignment. I do not believe that India can afford to be in a military pact either with Russia or with America. The pressures are just as great from either of these two power blocs. This is the truth of it. It is no use getting agitated over a newspaper report that Pakistan has been supplied with some jets because she had always had them.

There is another matter. There have been considerable negotiations, discussions, with various embassies and with various embassy officials and at the top political level over the supply of equipment to Pakistan. And at every stage, the question comes up that even if Pakistan has tanks, aircraft and other things, what is the stockpile of spares? You cannot run aircraft and tanks without adequate spare parts. And therefore, these are things which are very complicated and complex; it is a complex problem. I do not think that we can afford to create panic in the country over a newspaper item like this.

I think, on the other hand, that it is very necessary that the Government should go ahead more actively with the manufacture of aircraft, because we have the basic potential in the country for finishing the things which we had taken in hand. I would not like to go further into the details of this, but we cannot afford to rest content with just these Gnats.

Shri Nath Pai (Rajapur): Mr. Speaker, Sir I would like to plead with you, to start with, to be a little more indulgent with me today because it is very rarely that this House gets an opportunity of focussing attention on something which is a little far more vital than a newspaper report. Shrimati Sharda Mukerjee said that it was just a newspaper report. I always listen with great attention and respect to whatever she says on matters of our defence, but I am a little disappointed today, when she tried to dismiss this matter as a report published in a newspaper and therefore can be dismissed summarily.

The whole question of the supply of arms to our potential aggressors needs to be imported a new perspective. It needs to be put in its proper place. I am afraid the reaction, the approach of the Government of India to this problem has been an admission, has been a proclamation, of gullibility and naiveto. Its action has been an exercise in futility and self-deception. Somehow, the whole problem has been reduced to the absurd level of sending a very strong note to be followed by a stronger note. And then, Mr. Chagla persuades himself and wants to persuade the country that all that can be done has been done.

Mr. Chagla reminds me of a very dainty and delightful combination of the village schoolmaster and a delayed reincarnation of King Canute. He has the self-righteousness of the village schoolmaster and the self-importance of King Canute. I would like to tell you how dangerous this attitude can be in facing this problem. This is the way you have been reacting. Some arms are being poured, and we think that all our duty is discharged if we send protest notes to the United States and if we get some assurances from Bonne, or, when the occasion presents itself, an assurance from Teheran. How can he deceive himself with regard to these assurances?

I will now quote from his own words. After his triumphant tour of Teheran, Shri Chagla, speaking to the press, said—according to the national press—that the Iranian Government had assured him that it would not give any military aid to Pakistan or supply arms or armaments which might be used against India. Then he added that "We need not be apprehensive that Iran would militarily support Pakistan in the unfortunate eventuality of a conflict." This was a total incapacity to read the mind of the people whom he was calling upon, because in a few days, the Iranian Government contradicted it, and then, speaking in Parliament, Shri Chagla corrected himself by saying that "the Iranian Government told us that they would be obliged to help Pakistan in the event of aggression against her....It would indeed be unfortunate if military support were given to Pakistan against India."

When I see this combination of self-deception and self-righteousness, I am reminded of what Viswamitra said. When sage Viswamitra was eating the leg of a dog, a chandala said, "What is happening to the religion when the Brahmin is eating the meat, and that too of a dog?" And then Vishwamitra said:

पिबन्तेवोदकं गावो मण्डुकैरुपास्ति
न नेधिकारो धर्मेस्ति माभू आत्मप्रशंसकः

When a cow is thirsty, she goes to a pond and disregarding the pathetic protests of the frogs in the pond, goes on drinking all the water her stomach can hold. The sheer impotency of this perpetual posture, the perpetual posture of pathetic protests, has not yet dawned on the Government of India. Mr. Chagla and the Government of India somehow think that this is a problem like the problem of a naughty child, which is playing crackers and with the schoolmaster's atti-

tude, all that we have to do is to proclaim that it is naughty and should not be done, from the lofty heights of South Block, and everything will be all right if only we could do that.

I would like to read him something from the *New York Times* which has emerged as a major critic of some of the unsavoury activities of its own department and which has these revelations for its own countrymen and if the External Affairs Minister would care to listen, for our benefit. The arms supply is not something only diabolical. It has its roots and ramifications in something far deeper. It is directly connected with the long-term strategy of a country. If I may be permitted to say so, these are the imperatives and compulsions of what may be termed the competition to be a super-power—the super-powerism of our age. The United States has been the pioneer supplier of arms but we shall not get anywhere by indulging in this exercise of pathetic and impotent condemnation of what the US does. Why does it do it? Is it likely to stop by condemnation? If that were so, I would join my voice to that of Mr. Chagla. Therefore, I plead your indulgence because this is an aspect which has never been brought to the notice of the House.

This is what the *New York Times* says:

> "From mid-1949 through June of last year, the U.S. sold 16.1 billion dollars in weaponry and gave away an additional 30.2 billion dollars in arms and assorted military equipment. The 46.3 billion dollars total, which does not include private transactions arranged outside of Kuss's office—

I shall have something more to say about what it means presently—

> "is about a billion dollars more than the total of grants and loans under the regular economic assistance programme since mid-1948, including the Marshall Plan.'

During these 18 years, the USA has poured from its arsenal into the armouries of other countries—nearly 55—arms and ammunition and military equipment of the order of Rs. 28,000 crores. This is something important. How is it done? They are not hiding it. We are not to wait for the disclosure in the Senate Subcommittee. There is a regular department in the Pentagon which is called international logistic negotiations department and Mr. Kuss is only the Under Secretary there. These are the admissions then made. This forms part of the policy of the country. Who is to suffer? Who is to resist? Who is to benefit? The US will be following this policy. Why? This is an in-built imperative. It is like this. In the competition to remain "the power" in the world, in any case one step ahead of the Soviet Union, USA will be going in for the most modern equipment and weapons that modern science and technology can forge for its arsenal. Every five years, the generation of weapons which are modern today become outmoded. What are the Americans going to do? Naturally, the weapons which are modern today, after they become outmoded, after five years, are dumped on the markets of Western Europe and from there they percolate into the greedy hands of the under-developed countries. This is inevitable and this is what is happening.

The *New York Times* further says:

> "After Britain lost out to Kuss in a 37 million dollar tank sale to Italy in the spring of 1965, Prime Minister Wilson complained that the high-pressure salesmanship' of the Americans had 'unbalanced the situation in the Atlantic Alliance."

Even Britain could not stop this.

The Export-Import Bank has been another important source of credit for Mr. Kuss's activities of selling arms to those countries which want it.

> "According to Congressional testimony by senior Administration officials, the Bank, at the

[Shri Nath Pai]

> request of the Defence Department, has lent or committed itself to land 2.6 billion dollars to foreign countries for arms...."

25 per cent of the Bank's activities are covered by loans for purchase of arms by West European countries. This is the problem which is analysed in this brilliant analysis given in this paper.

The US has evolved no long-range policy to deal with the growing problem of surplus arms. Mr. Chagla, your experts and your colleague the Defence Minister, must see and take a long-range view. You cannot get away from your duty by saying that you have written a strong note and a stronger note is on the way.

Mr. Speaker: He should address the Chair.

Shri Nath Pai: Mr. Speaker, I will cite to you from the Hansard that it is absolutely coming through you, otherwise the words from the House of Commons: "Now, gentlemen, you have done enough harm to England and I ask you to quit" would never have been uttered because that would have meant, taking the literal meaning, asking the Speaker to quit which nobody ever asked. But I shall readily follow your guidance.

Now I come to the State Department. It is said here in this paper:

> "The State Department simply grapples with each case as it arises. American control over the ultimate use of weapons through agreements, however, tends to weaken as the surpluses accumulate."

This is the problem. We now see how what the United States is doing the Soviet Union is also doing. I will read from the report of the Institute of Strategic Studies, a latest document, reference to which was made by Shri Prakash Vir Shastri when he referred to one aspect of it. There it is said:

> "The supply by China to Pakistan of MIG-19 aircraft and T-59 tanks, plus earlier shipments to Cambodia of infantry weapons, indicates that China's armaments industry is recovering from the set-backs experienced in the early 1960s, when Soviet aid was withdrawn, and is progressively replacing its large quantities of obsolescent Soviet equipment."

And, it is this that she is prepared to give to the Arabs, it is this that she is giving for the re-equipment of the Pakistani Division stationed in Eastern Pakistan, it is this that she is prepared to give to poor African nations which are in need. Where do we stand in the context of all these things?

I will come to the solution. One solution will be that the Soviet Union and the Americans reach a viable agreement about a general disarmament and about a total ban on the supply of arms to other nations. That is one thing. But is it likely to happen? If it does not happen, where shall India stand? Will the legions of protest notes be a substitute for India's preparedness? Every hon. Member has pointed it out (*Interruptions*). Sir, I would rather like to improve upon it and give the latest picture. Pakistan received this equipment from the United States of America. Pakistan received complete equipment for six infantry divisions and an armoured division, eight squadrons of F-86 sabre jets, two squadrons of F-104 Starfighters, four or five squadrons of bombers and some transport planes. In the armour were M-47 and M-48 Pattons, M-24 Chaffee and M-41 Walker tanks, and about 1000 125 mm, 155 mm and 175 mm guns. She also received a complete long range radar screen for her frontiers, and air bases with underground hangars. Added to that, she has now received from China 4 squadrons of MIG-19 and an undisclosed number of Chinese tanks, but very important.

During the last 15 months Pakistan has received arms and equipment and modern weapons of the value of one billion dollars, and this is the exact break-up. She received 300 million dollars from Saudi Arabia as a loan. She raised on the London market 100 million dollars and she, through Levy Brothers in Toronto in Canada, raised another 96 million dollars. This makes a total of half a billion. Under the American pact of matching aid America gave another half billion. Therefore, in all she received one billion dollars worth of aid.

Where do we stand in the context of this kind of build-up? This is not simply a newspaper report. I am told by Sardar Swaran Singh—I have a plethora of statements made by him in this House and also the other House —that if anybody ventures to do aggression she will receive a hot reception. We duly appauld him. I know the Indian army is well prepared. But for what? To fight a second world war. The world is getting ready for the third world war and our preparation is for the second world war. The total naval preparation is pre-second world war wintage; our air force strength is Korean war wintage and our army is a museum piece, which has every equipment from 1905 onwards, of course with some equipments which are luckily of 1967 from Russia. This is our preparation and with this where shall we get?

I want Shri Chagla to take a long-term view of the whole problem. I am very glad to see that the Defence Minister is sitting here. I wish that even the Finance Minister is here, because a powerful foreign policy is not possible without internal strength, coming from our economic strength; nor is a powerful armed force possible without economic strength. The three are inextricably mixed up. But we never see in this divided House such co-operation. They are united only to defeat a privilege motion. So far as the long-term planning is concerned, there is never any such thing.

What should we do? I have never mentioned, for paucity of time, the dual threat on our frontiers. During the next ten years India will have the super-human task of guarding of three frontiers—the eastern frontier, the northern frontier and the western frontier—and this is a super-human task. What do we do?

I told you about our equipments. I do not want here to under-estimate the morale, the bravery, of our soldiers and the brilliant captaincy of our military high command. But there is one aspect. There are 10,000 brilliant Indian technicians and technologists who can transform our military preparedness and take it away from this kind of colonial status of dependance on shopping in the world market for out-dated arms. Even when in 1971 the MIG project is completed, we will have a gap of 12 years, compared with the rest of the advance world. If the MIG project comes through as per schedule, and there are many 'ifs' for that, India will be 12 years behind the rest of the world. So, I suggest this concrete thing. Either we retrieve India's lost prestige and influence and try to act as mediators between the Soviet Union and America so that they could come to a sensible understanding to stop this kind of racketting for arms or, what is more important, we turn home and give a little heed to what Shrimati Sharda Mukerjee has stated. I entirely agree with that; Professor Madhok put it more concretely. 10,000 brilliant Indian brains are working. Where? Not in the laboratories of India, but in nuclear development, in aeronautics, in supersonic development in other countries. The best Indian technicians, scientists and engineers are working in foreign countries and their talents, their skills, their experience, they are not available to this country. Call them back with vision. If you call them back, we will make a begining. I know that they will not call them back. But, Sir, you and I will have to put pressure on them so that they

[Shri Nath Pai]

will call them back. Let us, therefore, make this appeal to all those Indian technicians, scientists and technologists abroad to come back to India and help this country create the basis for India's preparedness, where we will be not depending on the chrity or mercy of this nation or that nation, but basically we will be depending on the resourcefulness of Indian arms and Indian strength, Indian unity and Indian courage. If this lesson is driven home, I think this debate will have served its purpose.

Shri K. R. Ganesh (Andaman and Nicobar Islands): Mr. Speaker, Sir, we are discussing a very serious matter affecting the national integrity of this country, and I think we, on this side of the House, are not behind our friends on the other side in realising the gravity of the situation. But I agree with my hon. friend, Shrimati Sharda Mukerjee that it is not necessary to create a climate of panic, to create hysteria, to create a climate of war, to depict as if we are in an absolutely blind alley, to depict as if this government and this country is not prepared to meet any aggression, any threatened aggression, if the Pakistanis have any idea about it.

I was very attentively listening to the thesis of my hon. friend, Shri Nath Pai, and out of all that he has said what is the alternate policy? I am afraid, in all his verbosity and in all his capacity for oratory and to cloud the issues the only alternative policy he gave was to get back 10,000 of our people who are outside the country and who will be able to revolutionise our defence. I do not think that that is a policy which will take us out of the present difficulties.

18 hrs.

It is a fact—I do not go into the details of it—thatPakistan is arming feverishly. It is also a fact that there are countries in the world which want to build Pakistan as a country of tension as far as this area is concerned. The difficulty with some of our friends over there, who day in and day out attack the foreign policy of this country, is that they do not realise and come to grips with this problem.

Why is Pakistan being built up as a power? Pakistan being a small country is not in a position to fight us. Pakistan is being built up to create tension in this part of the world.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): Israel's example is there.

Shri K. R. Ganesh: We cannot isolate the arming of Pakistan from the situation in Vietnam, Israel, Greece and Rhodesia.

He has himself said that according to the *New York Times* or the *New York Herald Tribune*—whatever it is; I did not get him—a billion dollar worth of rejected armaments, which as far as the United States is concerned have become outdated armaments, are being exported to the various developing countries which need arms. Our friends on that side of the House do not recognise that the military industrial complex of the United States wants to export their rejected armaments and thus create an area of conflict in various parts of the world. It is their strategy in Vietnam. It is their strategy of fighting by proxy. We have known that the United States has recognised the value of a limited war. They are fighting a limited war in Vietnam and in West Asia. They would like to build up tension in our area so that we, who are following a policy which is not in consonance with that of some of these powers, we who are trying to build up our own country and are trying to resist interference by powers whether on this side or on that side, are weakened either by internal subversion or by heavy investment or by using a country like Pakistan against our independence, foreign policy and the integrity of this country.

This is a matter which, I humbly submit, is a part of a global strategy of these powers. They are using that in various spheres. I may submit that I have had the opportunity just 15 days back to go to Stockholm for

the world conference on Vietnam. This industrial complex of the United States is the main reason for the Vietnam war and for various other wars that these countries are fighting by proxy.

Mr. Speaker: Come to India now. Your time is almost over. You complained that Shri Nath Pai did not give any concrete suggestion. Come along, now you give some concrete suggestion.

Shri K. R. Ganesh: I am not the only person who is talking irrelevant in this House. As you know, I am a new Member and I have heard so much irrelevant talking here that probably the little irrelevance from my side may kindly be pardoned.

Mr. Speaker: Go ahead; please conclude.

Shri K. R. Ganesh: I am trying to project a view-point which probably may not be acceptable to many Members. But it is a view-point which cannot be neglected because we will be failing in our duty if we do not recognise that the arming of Pakistan, the building up of Pakistan, is against the Independence of this country, both by China and America and other western powers who speak different languages, who start in opposite directions but come to the same conclusion and to the same effect. We will have to recognise this and have an alternative Indian policy. What can that policy be? That policy can only be that we build our own armed strength, our own armaments here. When we do that, our friends on the opposite side will get up and say, "We are spending more money." We cannot have both the things; we cannot spend more money on armaments, because we have to spend money on economic development and on solving the basic problems that our people are facing today within the economic conditions of today. Therefore, this Government, this country, is trying to follow a policy depending on the economic strength of our country.

Our friends opposite criticise the heavy industry that is being built here. You can realise, if this country and this Government had not built the heavy industry, the armament industry, what would have been the position when we faced Pakistan or when we faced China. Therefore, the only alternative policy is to build our own armament industry, to get arms from those countries which are prepared to sell arms to us without mortgaging our foreign policy, without mortgaging our Independence, and to build the economic strength of the country. The economic strength and the prosperity of the people will alone be able to meet the aggressor.

What is this climate of hysteria that is being created here? It is known that, as the hon. lady Member, Shrimati Sharda Mukerjee pointed out, these are the same weapons which Pakistan had when Pakistan attacked us in 1965. I do not think our friends on that side believe that in all these two or three years this Government has not made any preparation for the defence of the country.

श्री प्र० न० सोनंकी (कैरा) : अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में मैंने कांग्रेस सदस्यों को भी सुना और कुछ अपनी ओर के सदस्यों को भी सुना। उन को सुन कर मैं सोच में पड़ गया। हमारी समस्यायें बहुत हैं। श्री नाथपाई अभी हमारे लश्कर की तादाद बढ़ाने और हथियारों की पूर्ति के लिये कह रहे थे।

18.09 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मैं सोच रहा था कि एक तरफ हजारों भूखे लोग भी हैं जो रोजी रोटी की मांग कर रहे हैं, केवल लश्करी ताकत इकट्ठा करने की समस्या हमारे सामने नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सी समस्यायें हैं। या तो हम स्वयम् दुनिया का मुकाबला करने के लिये अमरीका और रूस की ताकत जैसी ताकत पैदा करें या फिर इस ओर ध्यान दें कि यह

समस्या हमारे लिये नहीं है । हमारे लिये सब से बड़ी समस्या यह है कि हम शान्ति-पूर्ण तरीके से इस देश में रह सकें । हमारे दो पड़ौसी चीन और पाकिस्तान हमेशा हम को परेशान करते रहते हैं ।

Shri P. G. Sen (Purnea): How long are we to sit?

Mr. Deputy Speaker: This is an important debate. I cannot just say because some more Members are to speak from both the sides.

श्री प्र० न० सोलंकी : हम शान्ति से रहना चाहते हैं । लेकिन हमारी उस शान्ति को दूसरे राष्ट्र भंग कर रहे हैं । मैं नाथपाई जी का इस बात में समर्थन करता हूं और उनकी इस बात को मानता हूं कि हमारा देश आज जिस ढंग से विरोधपत्र भेज रहा है और भेजता रहा है अमरीका और रूस आदि को, इस तरीके को छोड़ना पड़ेगा, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा । मैंने राज्य सभा में जो डिबेट हुई है और सरदार स्वर्ण सिंह और श्री चागला ने जो कुछ वहां कहा है उसको पढ़ा है । उन्होंने कहा है कि हम और कर ही क्या सकते हैं ? जर्मनी को हम रोक नहीं सकते हैं कि तुम पाकिस्तान को हथियार न दो, किसी और देश को हम रोक नहीं सकते हैं कि वह पाकिस्तान को हथियार न दे । मैं नहीं कहना चाहता हूं कि आप जा कर उनको रोकिये । उनको जितने हथियार देने हैं पाकिस्तान को देने हैं, पाकिस्तान की जितनी ताकत बढ़ानी है उतनी ताकत बढ़ाने दीजिये । लेकिन आप भी अपनी ताकत को बढ़ाइये । मैं मानता हूं कि हम अपनी ताकत को बढ़ा भी रहे हैं । लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है । अफसोस इस बात का है कि ये वे मुल्क हैं जो कि दुनिया भर में शान्ति के दावेदार बनते फिरते हैं । रूस और अमरीका यू० एन० के अन्दर न्युकेलियर डिसआर्मामेंट की बात करते हैं । मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों को पहले यह कह दीजिये कि यह जो आर्मामेंट वे पाकिस्तान का कर रहे हैं इसको रोकें फिर न्युकलियर डिसआर्मामेंट की बात करें । छोटे छोटे मुल्क, गरीब मुल्क जो आज अपने देशवासियों के लिए अनाज ढूंढ रहे हैं, अपने देशों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हथियार दे कर बार बार झगड़े में डाल कर वे दुनिया के साथ धोखा कर रहे हैं । यह उन बड़े देशों की हिपोक्रेसी है और इसको सामने लाया जाना चाहिये । हमारी सरकार को इसके बारे में आवाज उठानी चाहिये और इसके बारे में साफ साफ कहना चाहिये । अमरीका को भी कहना चाहिये और दूसरे देशों को भी कहना चाहिये । अमरीका को कहना चाहिये कि वियतनाम में आप शान्ति की बात कर रहे हैं लेकिन एक बात समझते नहीं हैं । वियतनाम का झगड़ा अब तक सोचा था कि वह खुद सम्भालेगा लेकिन क्यों नहीं सम्भाल सका ? क्या दक्षिण वियतनाम, कम्बोडिया और दूसरे राष्ट्र जो हैं वे मिल जुलकर नहीं रह सकते हैं । अमरीका ने सोचा था कि पाकिस्तान को वह जो हथियार दे रहा है उन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान चीन के खिलाफ करेगा, साम्यवाद के प्रसार को वह रोकेगा । लेकिन अमरीका आज बीस साल से इतना तक नहीं सोच पाया है इतनी बड़ी ताकत होते हुए भी, इतना बड़ा विदेश कार्यालय उसका होते हुए भी कि पाकिस्तान ने भारत के प्रति दुश्मनी को खत्म नहीं किया है लेकिन फिर भी वह अभी तक उसको हथियार दे रहा है । हमारी सरकार को अमरीका को कहना चाहिये कि आप लोग किस ढंग से सोच रहे हैं । हम तो जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन पाकिस्तान हमारे प्रति दुश्मनी की भावना रख रहा है । अमरीका यह नहीं सोच पा रहा है कि

उसने दो दो दुश्मन भारत की सीमाओं पर खड़े कर दिये हैं, चीन और पाकिस्तान और ये ऐसे दुश्मन हैं जो हमेशा हमारे साथ संघर्ष करते रहते हैं। अमरीका को हमें पूछना चाहिये कि उसे क्या चाहिये, डिक्टेटरशिप चाहिये, कम्युनिज्म चाहिये या अमरीका को हिन्दुस्तान जैसी डैमोक्रेसी को बढ़ावा देना चाहिये? इस सवाल को हमें अमरीका के सामने रखना चाहिये। इस सवाल को अमरीका के सामने रखने में हमें शर्म का अनुभव नहीं करना चाहिये।

दूसरी बात मैं गुप्तचर विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। बार बार इस विभाग की आलोचना होती है। भारत सरकार को महसूस होता है कि विरोधी पक्ष के लोग कुछ ऐसी बातें ला कर रख देते हैं जो कि देश हित में नहीं हो सकती हैं इन बातों को इस तरह से रखना चाहिये जिससे देश में खलबली न मचे, भगदड़ न मचे, घबराहट पैदा न हो। मैं समझता हूं कि इसका एक ही उपाय है और वह यह है कि कि हमारी सरकार गुप्तचर विभाग को कार्यक्षम बनाये, उसको बढ़ाये, उसको इस काबिल बनाये ताकि जो खबरें हैं वे हमें समय पर और सही मिलती रहें। आज तक हमें कहीं और से ही खबरें मिलती रही हैं, अखबारों से मिलती रही हैं, दूसरे सोर्सिस से मिलती रही हैं। 1962 में हर पर हमला हुआ, हम लापता रहे, हम बेखबर रहे। 1965 में काश्मीर में जब मुजाहिद घुस गए तब हम बेखबर रहे। हर बार हमें किसी और ने ही इन वारदातों के बारे में बताया और इस बात को आपको भी स्वीकार करना पड़ा है। मैं समझता हूं कि इस में विरोधी पक्ष ने कोई गलत काम नहीं किया और आपको बेइज्जत भी करना उसका उद्देश्य नहीं था। लेकिन आपको बेइज्जती सहन करनी पड़ी है इसलिए कि आपको खबरें नहीं पहुंचती और समय पर नहीं पहुंचती और इसका नतीजा यह हुआ है कि आप तैयारी नहीं कर सके हैं और समय पर उनका मुकाबला नहीं कर सके हैं। मैं चाहूंगा कि जो गुप्तचर विभाग है उसको आप बढ़ायें और उसको माडर्न बनायें, उसको ऐसा बनायें ताकि जैसे हमारी खबरें पाकिस्तान को और चीन को जा रही हैं, वे न जा पायें और उनकी खबरें हमें पहुंचती रहें। हम सावधान और तैयार रहें।

अमरीका आज पाकिस्तान में बेसिस बना कर बैठा हुआ है। उस के लिए वह पाकिस्तान को एक बिलियन डालर वार्षिक दे रहा है। पाकिस्तान अमरीका से भीख नहीं मांग रहा है। यह उसका हक है। वह कहता है कि आपका बेस हमारे मुल्क में है हम को इसका पैसा दो, किराये के रूप में दो किसी भी रूप में दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बेस को खत्म करो। हमें अमरीका को कहना चाहिये कि आप तो शान्ति की बात करते हैं। तब आपने इस बेस को क्यों रखा है। उसको रख कर आप पाकिस्तान को जो पैसा देते हैं उस पैसे को इस्तेमाल पाकिस्तान भूखों के लिए अन्न के लिए नहीं करता है, वह पैसा भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए हथियार खरीदने में खर्च होता है। ऐसे बेसिस को रख कर किराये के बहाने या और किसी बहाने पैसा पाकिस्तान को मिल रहा है। जितनी सहायता हमें आज तक नहीं मिली है उतना पैसा वह बेसिस रख कर पाकिस्तान को दे चुका है। दुनिया का सारा पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए, उससे हमें जलन नहीं होगी। लेकिन ऐसी बातों के लिए जिम्मेदार राष्ट्र अमरीका और रूस जिस तरह से हमारे साथ बरताव कर रहे हैं उस पर मुझे अफसोस है।

ताशकन्द करार के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं। आप रूस से पूछिये कि ताशकंद करार का क्या हुआ? मैं चागला साहब से पूछता हूं कि ताशकंद करार जब आपने किया तब क्या पाकिस्तान में पूर्ण विश्वास रख कर किया था। नहीं। दूसरे

[श्री प्र० न० सोलंकी]

लोग बीच में पड़े थे, उन पर हमने भरोसा किया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ शान्ति करो, तब वह हुआ था। एक दफा अमरीका ने ऐसा करवाया था और दूसरी दफा रूस ने। हम तो ताशकन्द समझौते की शर्तों को और जो उसके पीछे भावना है उसका निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसा ही कर रहा है। इस बात को आप रूस से पूछिये। वह इस समझौते का पालन करे, इसके लिए रूस क्या कर रहा है। यह रूप की जिम्मेवारी है। ताशकंद करार पर दस्तखत करवाने के साथ उसकी जिम्मेवारी पूरी नहीं हो जाती है। जो बड़े राष्ट्र हम को आ कर सीख देते हैं कि हमें शान्ति से रहना चाहिये वे ही शान्ति भंग का कारण बने हैं जो शान्ति के लिए अपना उत्तरदायित्व निभाने की बात आती है तो वे खिसक जाते हैं और जो परिणाम होते हैं वे हमें सहन करने पड़ते हैं।

मैं चाहता हूं कि इन बातों पर आप विचार करें। कोई ठोस कदम आप उठायें। तभी हम शान्ति से रह कर अपने मुल्क के जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ कर सकेंगे।

Mr. Deputy-Speaker: I would like to call a few more Members, some from the Congress side and some from the Opposition side, but on one condition, namely that they will have to finish in five minutes each.

श्री चंद्रजीत यादव (आजमगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त चीन और पाकिस्तान और खास तौर से पाकिस्तान की तरफ से जो फौजी तैयारी की जा रही है, उसको लेकर रोष व्यक्त किया गया है। किसी भी देश को अपनी स्वतन्त्रता की हिफाजत खुद ही करनी होती है। जब दुश्मन इस प्रकार से तैयारी कर रहा हो तो देश के अन्दर और देश की प्रतिनिधि सभा, इस संसद् के अन्दर उस पर चिन्ता का व्यक्त किया जाना स्वाभाविक है, रोष का व्यक्त किया जाना स्वाभाविक है।

लेकिन विरोधी दलों के नेताओं के भाषणों को सुन कर मुझे अत्यन्त खेद हुआ है। खेद इस वास्ते हुआ है कि आज इस सदन के अन्दर एक प्रकार से इस तरह की तसवीर खींचने की कोशिश की जा रही है गोया हम निर्बल देश हैं, गोया हिन्दुस्तान अपनी सरहदों पर जो खतरा उपस्थित है उसके प्रति जागरूक नहीं है, गोया हिन्दुस्तान गपनी आजादी की रक्षा करने की सामर्थ्य अपने अन्दर नहीं रखता है, क्षमता नहीं रखता है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें कह कर देश के मनोबल को तोड़ना, देश के अन्दर एक निराशा का वातावरण पैदा करना देश के अन्दर पस्त हिम्मती पैदा करना, उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करना खुद अपने को कमजोर करने के बराबर है। यह सही है कि हमारे ऊपर चीन ने हमला किया था और उस वक्त हम अपने देश की समस्याओं को हल करने में लगे हुए थे। हम को इस बात की चिन्ता थी कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें और देश की गरीबी को, देश के पिछड़ेपन को दूर करें। इन समस्याओं को हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। उस समय हम मिलिटरी देश नहीं बनना चाहते थे। हम अपनी फौज को नहीं बढ़ाना चाहते थे। हम चाहते थे कि दुनिया के अन्दर शान्ति कायम रहे। हम चाहते थे कि हिन्दुस्तान अपने पड़ोसियों के साथ शान्तिपूर्ण तरीके से रहे और अपनी समस्याओं को हल करे। जब हम इस नीति पर चल रहे थे तब हमारे साथ एक दगा हुआ, चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंका। हमने उससे नसीहत ली और महसूस किया है कि जहां हमको देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है वहां हम को देश की

आजादी की भी रक्षा करनी है और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमें तैयार रहना है। हमने तैयारी शुरू की। जब पाकिस्तान ने दुनिया के साम्राज्यवादियों द्वारा दिये गए हथियारों से हमारे देश पर हमला किया तो जो बहादुरी हमारे जवानों ने दिखाई उसको भुलाया नहीं जा सकता है। मैं प्रकाशवीर शास्त्री जी से कहना चाहता हूं कि देश की रक्षा करना कांग्रेस सरकार की ही केवल जिम्मेदारी नहीं है। यह कहा जाता है कि देश की 60 परसेंट स्टेट्स में से शासन की बागडोर कांग्रेस के हाथ में नहीं रही है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर देश की आजादी और स्वाधीनता पर हमला होगा तो देश की राष्ट्रीय एकता पर वह हमला होगा और सारा हिन्दुस्तान एक व्यक्ति की तरह से खड़ा हो कर उसका मुकाबला करेगा और अपने देश की सक्षा करेगा। यह है वह वातावरण जो हमें देश में पैदा करना चाहिये।

पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था। तब मैं सरहदों तक गया था, वहां तक गया था जहां तक हमारे फौजें गए थे। लाहौर की मैं उस सीमा तक जहां तक हमारे जवान गये थे, गया था। मैंने पिल बाक्सिस को देखा। मैंने पैटन टैंक को देखा। ये वे पैटन टैंक्स थे जिन को दे कर अमरीका ने कहा था कि जिस राष्ट्र के पास ये पैटन टैंक होंगे दुनिया की कोई शक्ति उसको पछाड़ नहीं सकती है। लेकिन हमारे देश के बहादुरों ने, हमारे देश के बहादुर सिपाहियों, हमारे देश के नेतृत्व ने, हमारे देश के फौजियों ने बहुत अच्छी तरह से उनका मुकाबला किया और हमारे बहादुर नौजवान सैनिकों ने हैंड ग्रेनेड्ज फेंक कर उनको तोड़ कर रख दिया और देश की रक्षा की। मैं जानता हूं कि केवल हथियारों से देश की रक्षा नहीं होती है। अमरीका के पास सब से आधुनिक शस्त्र हैं लेकिन वह कोरिया में मात खा गया, उसकी पांच लाख जो सेना वियतनाम के अन्दर है, उस के पास आधुनिक शस्त्र होते हुए भी, छक्के छूट रहे हैं। देश की रक्षा करते हैं देश के नौजवान देश की जनता, देश का मनोबल, देश की एकता और देश का राष्ट्रीय सम्मान और गौरव। इस प्रकार की जागृति आज हमें अपने देश में पैदा करनी है। आज जब कि हमारी सीमाओं पर हमले का खतरा है, जबकि एक तरफ पाकिस्तान हमारे विरुद्ध खड़ा है और दूसरी तरफ चीन खड़ा है और जबकि दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतें इन को इस्तेमाल कर के हमारे आर्थिक विकास में बाधा डालना चाहती हैं, हमारे प्रजातन्त्र को खतरे में डालना चाहती हैं और हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को छिन्न भिन्न करना चाहती हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने देश में मायूसी का वातावरण पैदा न करें। माननीय सदस्य प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और सुरक्षा मंत्री के साथ बैठें उन को हमारी कमजोरियों के बारे में बतायें और उन को अपनी सलाह और परामर्श दें। हम उन को आश्वासन देना चाहते हैं कि ऐसे प्रश्नों पर कोई पार्टीबाजी नहीं होगी, कोई राजनीति नहीं चलाने दी जायेगी। हम सब मिल कर देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद दें।

मैं आपके माध्यम से अपने मित्रों से यह अपील करना चाहता हूं कि वे देश में पस्त-हिम्मती का वातावरण पैदा न करें। हमारे देश के सामने जो खतरा है, सरकार उस से पूरी तरह आगाह है और उस का मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

लेकिन मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जो लोग इस सदन में विदेश मंत्री और हमारी वैदेशिक नीति का मजाक उड़ाते हैं, वे वही लोग हैं, जिन्होंने आजादी के बाद कभी भी हमारी नान-एलाइनमेंट की नीति को नहीं माना है, जिन का विश्वास विश्व-शान्ति में नहीं है, जिन को उसी अवस्था में सन्तोष होगा, जबकि हम प्रो-अमरीकन हो जायें, अमरीका की गोद में बैठ जायें, अपने देश की रक्षा के लिए बाहर से फ़ौज मंगा लें और विदेशी "छतरी" का इन्तजाम करें। हम जानते हैं कि ऐसे लोग मौके-बेमौके हमारी नीतियों पर हमला करते हैं, उस का मजाक उड़ाते हैं।

अगर विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को हवाई जहाज देने के संबंध में ईरान से बात की, तो क्या गलती की? अगर उन्होंने पाकिस्तान को स्पेयर पार्ट्स देने के विरुद्ध अमरीका को प्रोटेस्ट नोट दिया, तो क्या गलती की? अगर हमारे सुरक्षा मंत्री ने इस सदन को आश्वासन दिया कि हमारी फौज तैयार है और अगर हम पर हमला होगा, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे, तो उन्होंने क्या गलती की? अगर इन बातों का मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है, तो यह दृष्टिकोण घातक है, इस दृष्टिकोण से हमारा देश कमजोर होगा।

अन्त में मैं अपने मित्रों से यह अपील करना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय एकता, हमारी सरहदों की रक्षा और हमारी आजादी की रक्षा एक राष्ट्रीय सवाल है, इस लिए हम सब अपने मतभेद भुला कर इन के संबंध में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनायें और सब मिल कर देश की सुरक्षा को मबूजत बनाने में अपना योगदान करें।

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta North East): I would like you; Mr. Deputy-Speaker, if you do not mind, to convey to the Speaker my feeling that it is somewhat unfair that some of us are being pinned down to five-minute speeches when quite a number of other members are permitted to make voluble declamations.

Mr. Deputy-Speaker: It is not the Speaker's suggestion. As I see the time, we have got to set some limit. No protest is called for. If you co-operate, I will accommodate some more members—that is all.

Shri H. N. Mukerjee: I shall try my utmost in the line of co-operation, but I have discovered, as Shri Chagla has discovered, not only in Parliament but in international relations, that politeness does not pay. In any case, the discussion that is taking place today has a very limited objective and there is no reason for me . . . (*Interruption*) I do not know if Parliament becomes a shambles to this extent. There is no need to indulge, as some of my friends did, in the delectable exercise of trying to pull Shri Chagla's somewhat outspread legs, but it is necessary for us today to find out as to whether the revelations which were made on the 26th July should be allowed to be explained away. I do not like the idea of Shri Chagla saying rather innocently that he has got certain assurances from the West Government and that he had no other alternative than to believe it. In that regard I say that what the West German Government has been doing, in spite of whatever denials it might be putting forward, is a continuation of a policy which it has been pursuing at least in regard to the supply of arms to Pakistan since 1964-65 in a more blatant fashion.

Last summer, in 1966, there was a report in the European press of a secret military agreement amounting to 200 million Marks which, apart from the supply of Cobra anti-tank missiles, already used in battle during the Indo-Pak. conflict, stipulated for delivery of

equipment of a plant producing the missiles, for the supply of tanks and aircraft of the types of F-36 and F-84, of artillery guns, radar equipment, technical knowhow for rocket launching pads etc., between West Germany and Pakistan.

As far as Mr. Chagla is concerned, he has told us that if private parties supply arms to Pakistan, he has no control over it. The Government in Bonn has taken no step yet to stop armament despatch to Pakistan by the German citizens, and through this channel a large number of weapons have arrived, according to reports which come to us, into Pakistan. Whether it is to Iran or Pakistan is more or less identical, as the Defence Minister admitted the other day. It is a kind of difference which we need not bother about. And this Government of West Germany has been behaving so egregiously in regard to that, that that is accepted as the lesson which we ought to draw.

I think a Congress Member of Parliament of this House or the other House, I am not very sure, has supplied to the Government, to the Prime Minister herself, as far as my information goes, a photostat which showed how the International Press Service of West Berlin on 7th December, 1966, released a very tendentious report regarding a new State comprising East Pakistan, West Bengal, Assam, NEFA, Nagaland, Tripura and Manipur, Sikkim and Bhutan, and added that authoritative Western commentators thought that this might help to solve the critical problems arising in the Indo-Pakistan sub-continent. This is the way in which the West German Government is functioning.

The chauvinists, the revenge-seekers of West Germany had met at a meeting at Kiev last year in September and made a declaration about us. "We do not understand", they said, "why we grant a country thousands of Marks when it states that two German States exist." Jawaharlal Nehru's fault was that he had referred to the existence of two German States.

I say, therefore, that this kind of conduct on the part of the West German Government should make us relinquish whatever obligations we imagine exist on us in pursuit of what used to be called the Hollstein doctrine.

That doctrine itself is crumbling. Bonn has annulled its insolent pretension to the doctrine so far as relations with socialist countries are concerned, but Bonn still says that the doctrine stands in so far as Asia, Africa and Latin America are concerned. We are second class or third class States with no sovereign rights, and we have to okay whatever line comes to us from certain quarters of the world.

This Government, as has been pointed out by some friend on the Congress side, has been on the side of the oppressors of the people. It supports American aggression in Viet Nam. It collaborates closely with the apartheid regime in South Africa and the racist bandits of Rhodesia. It gives aid to Portuguese terrorist campaigns against the African people. And the latest instance of its conduct is that, together with Israel, it plotted and fought savagely against the Arab peoples, and is going on with that fight still. And that is the kind of country with which we have such relations, and the country has behaved in the manner that it has in regard to arms supplies to Pakistan.

We want friendship with Pakistan, we stand by the Tashkent Agreement, no doubt about it, but we wish to keep our powder dry, and we do not want to see that those patrons of Pakistan, for their own imperialist reasons, build up Pakistani strength as against India, retain and develop the animosity between the countries which can be manufactured and incited, because of the presence inside of us of certain elements which are not particularly desirable. It is something which we

[Shri H. N. Mukerjee]

ought to understand. On the other hand, there is the German Democratic Republic with which our friendship is genuine, with which our relations are to develop. In the German Federal Republic, the government led by Bonn, there was published last year a book called "India, with or without miracles". It was as a matter of fact published at Stuttgart, published with the sanction from the then Bonn Ambassador to India, Dr. Melchers. I am quoting an expression which is used in that book:

> " 'It would be wiser to build gas chambers for 400 million Indians instead of gas furnaces'—I once overheard a particularly tactful foreman in Rourkela."

That is the kind of thing they say about our country. On the contrary with the GDR we have friendship; our economic relations are growing. Their Prime Minister came to this country in 1959. To all outward appearances our relations are very close and friendly but because of the miserable existence of this Holstein doctrine, this scare-crow of a doctrine which has no business to pollute international atmosphere, we are afraid and we do not want to heighten our relations with GDR. We do not even open a Consulate-General in East Berlin; we do not even give our trade representative in GDR the same status as the trade representative of the GDR has got in this country. Therefore, I suggest to the External Affairs Minister—he and the Defence Minister are here—we should draw the lessons from that kind of thing. We should not in an innocent fashion believe in the kind of repudiation which has come from Bonn. We should get our information through our Embassy which in this regard has shown the most inept record. We should draw our lessons and act in the international sphere accordingly. We need not kotow to Bonn. We should have relations with the two Germanys, the existence of which we recognise, on a level which is consistent with the dignity of our country as well as international relations.

श्री राम किशन (होशियारपुर): डिप्टी स्पीकर महोदय, पिछले चन्द हफ्तों से जो अखबारात के अन्दर खबरें आ रही हैं वह काफी तशवीशनाक हैं। वैसे तो पाकिस्तान ने सितम्बर 1965 में करारी शिकश्त खाने के बाद पिछले दो साल में जितने भी इस संसार के इंटरनेशनल गन रनर्स बिजनेस हाउसेज हैं उन तमाम से उसने अपने सारे रिसोर्सफुल एजेंट्स के जरिए पूरी तरह से अपनी वार मशीन को मजबूत करने की कोशिश की है। यह काफी तशवीशनाक बात है। इसके अन्दर कोई शकोसुबहा की बात नहीं। और उसके साथ साथ जो पिछले दिनों 96 घंटे की लड़ाई हुई इसराइल और वेस्टर्न एशिया के अरब कन्ट्रीज में उसने कुछ मिलिटरी और पोलिटिकल लेसन्स हमारे लिए छोड़े हैं और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया उससे पूरी तरह से खबरदार है।

तीन चार बातों की तरफ मैं आपके जरिए अपने डिफेंस मिनिस्टर और फारेन मिनिस्टर की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। ताशकंद मुआहिदे के बाद जब फौजें हटीं तो पाकिस्तान को एक बात का हमसे कुछ ज्यादा सुभीता हासिल है। हमने सीज फायर को पूरी तरह से माना। सीज फायर के एग्रीमेंट के मुताबिक जहां तक फौजों का ताल्लुक है वह कोई 15–20 मील के फासले पर ठहरती हैं और साथ ही कुछ वोर्डर पोस्ट्स वगैरह होती हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और सारे हाउस को मैं समझता हूं इसका इल्म होना चाहिए कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसकी फौजें इस वक्त कहां खड़ी हैं? स्यालकोट सीज फायर लाइन

के चार मील के फासले पर है, गुजरात 12 मील के फासले पर है, खारियां 8 मील के फासले पर है और मर्री 16 मील के फासले पर है जहां उसके सबसे बड़े हवाई अड्डे हैं जिन्हें सेंटो ने पूरी तरह से अपना पैसा दे कर बनाया है। फौजें वहां उसकी अपनी हैं। और यह वह इलाका है जिसको पिछले दिनों की खबरों से पता चलता है कि उन्होंने सिविल पापुलेशन से पूरी तरह से इसे निकट से खाली कराया है। गुरिल्लाज, इन्फिल्ट्रेटर्स और मुजाहिद व अन्सार को पूरी तरह से ट्रेन कर के वहां भेजा है। ईस्ट बंगाल में उसने अपने हवाई अड्डे बनाए हैं जहां चाइनीज ने पूरी तरह से मिग्स जहाज चलाने की ट्रेनिंग दी है। यह ऐसी बाते हैं जिनसे हम इन्कार नही कर सकते। काफी तशवीशनाक हैं और इन सब बातों को पूरी तरह से हमें मुकाबिला करना होगा। पिछले दिनों पाकिस्तान का डिफैंस बजट जो पेश हुआ उसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने अपना डिफेंस का बजट काफी कम किया है कुल 218 करोड़। लेकिन उसके सारे डिटेल्स के अन्दर जाया जाय तो वह 218 करोड़ के बजाय 400 करोड़ रुपये का बजट है। 57 परसैंट उसके बजट का डिफेंस पर खर्च हो रहा है। इन बातों पर मैं नहीं जाता कि कहां से उसने क्या किया कहां से नहीं किया। लेकिन इन सारी बातों की तरफ हमें ध्यान देना होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके मार्फत मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे देश का ताल्लुक है इसरायल की लड़ाई ने क हमें सबक दिया हैं और वह सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारी ऐयर पोर्टस न सिर्फ वैल डिस्पर्स्ड ही नहीं होनीं चाहिएं बल्कि वेल प्रोटेक्टेड होनी चाहिएं और सरप्राइज अटैक के लिए पूरी तरह से उसके मुकाबिले के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कोई भी नेशन इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बात का भी हमें पूरी तौर से निश्चय है कि पिछले दिनों जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान ने अपना सारा कुछ दांव पर लगा दिया था। उसका हिन्दुस्तान के बहादुर जवानों ने और खास तौर से पंजाब के बहादुर जवानों ने मुकाबिला किया था। उस वक्त चीन के दिमाग का, अमेरिका के हथियारों का और पाकिस्तान के जवानों का मुकाबिला किया था पंजाब के उन बहादुर जवानों ने और मुझे पूरी तरह से निश्चय है कि वह आगे भी मुकाबिला करेंगे, हिम्मत के साथ मुकाबिला करेंगे। मैं इतिहास के पन्नों को बदल नहीं सकता हूं। इतिहास के पन्ने यह बताते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का नतीजा क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार का नतीजा हुआ था कि जार और कैसर खत्म हुए थे, दुनिया के अन्दर से बादशाहत खत्म हुई थी। सैकैंड वर्ल्ड वार का नतीजा हुआ हिटलर और मुसालिनी जैसे डिक्टेटर खत्म हो गए। अगर यह थर्ड वार हमारे ऊपर थोपी जाती है, हिन्दुस्तान एक पीसफुल देश होते हुए भी अगर यह दुनिया के दो डिक्टेटर माओ–त्से–तुंग और प्रैसीडेंट अयूब, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को कुचला चाहते हैं और उस पर हमला करते हैं तो मुझे इसके अन्दर रत्ती भर कोई शक नहीं है कि हिन्दुस्तान के वह जवान जो 1965 के अन्दर सागर पर लड़े थे, धरती पर लड़े थे, आसमान में लड़े थे, और उन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाये थे वह अब भी इनका मुकाबिला करेंगे और इन डिक्टेटर्स की पूरी तरह से शिकारत होगी। इसके अन्दर रत्ती भर कोई शक व सुबहा नहीं है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, हमें इन सारी बातों के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जब मैं तैयारी की बात करता हूं तो उसके मुताबिक इस नेशन को नेशन ऐट आर्म्स करना होगा। मैं नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान वार मौंगर बने

[श्री राम किशन]

लेकिन वार कौंसल तो होना चाहिए। हमें इस से इन्कार नहीं करना चाहिए और इस देश के अन्दर सब से पहली बात जिसकी तरफ़ मैं अपोजीशन के दूसरे भाइयों की तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह यह है कि ऐसी गम्भीर स्थिति के अन्दर नेशन को एक आवाज में चलना होगा, नेशन को एक कदम से चलना होगा, नेशन को एक झंडे के नीचे चलना होगा। नेशन को सेल्फ कांफिडेंस की बात करनी होगी। नेशन को पस्त-हिम्मती की बात नहीं करनी होगी। जो कुछ भी आज हो रहा है जो आर्मामेंट रेस हो रही है, जिस तरह से पाकिस्तान एयर फोर्सेज बढ़ा रहा है, जिस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पर एयर बेसेज को पाकिस्तान अमेरिका को देकर और वहां से पैसा वगैरह इकट्ठा करके पूरी तरह से उन्हें बना रहा है, और जो कई तरह की अफवाहें हिन्दुस्तान के अन्दर चल रही हैं में आशा करता हूं कि जहां तक गवर्नमेंट आफ इंडिया का ताल्लुक ई डिफेंस मिनिस्टर और फारेन मिनिस्टर का ताल्लुक है, वह अपनी सारी शक्ति को, सारी ताकत को, तमाम रिसोर्सेज को, इस बात के लिए लगायेंगे कि अगर हमारे इस देश की इन्टैग्रिटी पर और इस देश की टैरीटरी पर किसी तरह से कोई हमला करता हें, हम शान्ति चाहते हैं, लेकिन आज वह जमाना आ गया है कि हम शान्ति चाहते हुए भी अगर हमारी इन्टैग्रिटी पर कोई हमला करेगा, तो उसे हमें यह कहना होगा कि हम शांति चाहते हुए भी जंग के लिए, हर मौके के लिए तैयार हैं और उसका पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। तभी हम इस देश की रक्षा कर सकेंगे।

श्री रवी राय (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिस सवाल पर चर्चा चल रही है उस सिलसिले में पहली बात हमें यह कहनी है कि हिन्दुस्तान की विदेश नीति का कोई सपना नहीं है कोई बचार्यवाद भी नहीं है। असल में जिस चीज पर आज बहस चल रही है यह पिछली 26 तारीख को वेस्ट जर्मनी की सरकार की ओर से ईरान के जरिए पाकिस्तान को जो आर्म दिए जा रहे थे उस सिलसिले में चल रही है। असल में उस दिन चागला साहब ने थोथी दलील दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज को साबित करना चाहता हूं कि वेस्ट जर्मनी की सरकार ने हमारे छागला साहब को जो यह समझाया है कि जर्मनी की ओर से ईरान के जरिए पाकिस्तान को अमेरिका के आर्म्ज नहीं जाते हैं, यह ग़लत है उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ता० 28 को जो खबर निकली है जिसमें यू० एस० स्टेट्स डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी—रौबर्ट मैक्लोसकी से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या अमरीका के आर्म्ज पाकिस्तान को बौन के जरिये गये हैं तो उन के जवाब को सुन कर आप ताज्जुब में पड़ जायेंगे —

"I do not want to answer the question in the abstract", said Mr. Robert Macloskey. Mr. Robert Macloskey yesterday declined to say whether USA would allow West Germany to sell American tanks to Pakistan."

असल में उपाध्यक्ष महोदय, सवाल दूसरा है। इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं हैं कि अमेरिका के आर्म्ज पाकिस्तान की बौन और ईरान के जरिये भेजे जा रहे हैं—इसके लिये दो और प्रमाण भी हैं। स्टेट्समैन में ता० 28 को जो बयान निकला है

Informed sources said that the closely guarded deal has been approved at key points in the US policy-making machinery after a prolonged controversy but has now been temporarily stalled pending the outcome of angry congressional hearings on world-wide American arms sale policy.

इसके बाद कहा जाता है—

The transcript of the remarkable Senate Committee hearings contains the revelation by Mr. Samuel

Cummings, an international arms merchant, that Iran has signed recent agreements with three arms brokers—Vero of West Germany, Hamid Khan of Pakistan and Levy Brothers of Canada—in the hope of obtaining tanks from German stocks of US surplus.

यह ता० 29 का बयान है जिससे साफ साबित होता है कि बौन और ईरान के जरिये पाकिस्तान को हथियार गये हैं। लेकिन हमारे विदेश मंत्री बौन के आश्वासन से आत्म सन्तोष ले रहे हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश की विदेश नीति का कोई आधार नहीं रह गया है, कोई नीति ही नहीं है, दुनिया के सामनेहम आज हास्यास्पद हो गये हैं। असल में बात दूसरी है—1946 में जर्मनी हार चुका था, जापान हार चुका था, उस समय यदि हमारे यहां कोई प्रधान मंत्री होता तो कहता कि जर्मनी हमारा भाई है, हारा हुआ है तो क्या है, हर एक प्राणी समान है, इस चीज को यदि दुनिया के सामने उस वक्त रखा जाता, तब शायद स्थिति दूसरी होती तब शायद जर्मनी हमारे जीवन-मरण का साथी होता। इस सदन में छागला साहब बीस बार कह चुके हैं कि हम जर्मनी की सहायता के लिए बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, लेकिन फिर भी जर्मनी पाकिस्तान की सहायता करता चला जा रहा है।

जैसा लेनिन साहब ने किया था कि जितनी साम्राज्यवादी संधियां थीं उनको फाड़ दिया था, शायद हिन्दुस्तान का कोई हमारा प्रधान मंत्री होता तो वह कहता दुनिया को कि जितनी साम्राज्यवादी संधियां और करार हैं, उनको खत्म कर दो, ताकि दुनिया का जापान और जर्मनी के साथ रिश्ता अच्छे ढंग का होता। आज जब पाकिस्तान का सवाल हमारे सामने आता है कि हम पाकिस्तान को कब खत्म करेंगे, हम तब खत्म करेंगे जब हमारे सामने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का आखिरी तौर पर एक महासंघ बने, और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के हिन्दू मुसलमानों में एकता, सामिप्य और एक-बद्धता आये, तब पाकिस्तान की स्थिति को हम खत्म करेंगे। लेकिन इस सिलसिले में मैं छागला साहब को कहना चाहता हूं कि इस वक्त वह सिर्फ बौन के आश्वासन पर निर्भर न करें, हमारी जो कूट-नीतिक लोग हैं, हमारी जो एम्बेसीज हैं, व लोग क्या खबर देते है, उस पर निर्भर करें और उसको दृष्टि में रखते हुए हिन्दुस्तान को एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए पहल करनी चाहिये।

Some hon. Members *rose*—

Mr. Deputy-Speaker: Shri Randhir Singh—he may conclude his remarks in two minutes.

Shri Sonavane (Pandharpur): Sir, I rise to a point of order. Under rule . . .

Mr. Deputy-Speaker: I know the rule. The hon. Member may please resume his seat.

Shri Sonavane: Sir, how long are we to sit. I would request you to go by the rules. We are tired. There has been sufficient debate. Therefore, under Rule 193, I suggest that the hon. Minister may be called upon to reply to the debate.

Mr. Deputy-Speaker: I know the rule. Ultimately, I must be satisfied that there has been adequate debate and all points of view have been represented. It is not a question of getting tired. Perhaps the hon. Member is tired. Hon. Members must have enough patience when we are discussing subjects of this nature.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब,

न सम्भलोगे तो मिट जाओगे ए हिन्दोस्तानवालों,
हमारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में।

मैं कोई जजबाती बात नहीं कह रहा हूं सूरज मशरिक के बजाय मगरिब

[श्री रणधीर सिंह]

सकता है, लेकिन पाकिस्तान शरारत किये बगैर बाज नहीं आयेगा—यह मैं नहीं कहता हूं, यह खानबादशाह कहते हैं, खान अब्दुल गफारखां आज काबुल में बैठे हुए कहते हैं जो अहिंसा के अवतार हैं। अगर हिन्दुस्तान बारह काश्मीर भी तशतरी में रखकर पाकिस्तान को पश करेगा तो भी वह डंक मारने से से बाज नहीं आयेगा। मैं कौम परस्त आदमी हूं, फिरकापरस्त नहीं हूं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो पिछली लड़ाई में हारा था, वह एक जख्मी सांप की तरह से बदला लेगा और वक्त पर डंक मारेगा। पाकिस्तान चाहे न लड़े, लेकिन पाकिस्तान को लड़ानेवाला खूंखार अजदहा चीन कभी नहीं चूकेगा।

मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारी डिफैन्स की तैयारियों का ताल्लुक है, मुझे पता है कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर एक जंगजू डिफेंन्स मिनिस्टर है, कमजोर दिल आदमी नहीं है। उस के साथ हमारी बहादूरतरीन फौज है, और बगैर हथियारों के हम ने मुंह तोड़ दिये हैं, एक दफा नहीं पचासों दफा तोड़े हैं, लेकिन मै वार्निंग करना चाहता हूं कि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिये, उस का मुकाबला करने के लिये शिकारी को अपने यहां पूरे हथियार रखने चाहिये। आज ईसराइल की लड़ाई के बाद दुनिया का नक्शा बदल गया है। छोटे देश जापान ने नाक पीट दिया रूस का, छोटे देश कोरिया ने नाक में दम कर दिया अमेरिका का, छोटे देश क्यूबा ने सीधा बना दिया अमरीका को, छोटे छोटे देश ईजराइल ने नासिर का दिमाग ठीक कर दिया, मैं कोई तान में नहीं कहता हूं। आपको पाकिस्तान को छोटा नहीं समझना चाहिये, यह घुरड़िया सांप है।

अब एक बात कह कर मैं खत्म करना चाहता हूं। मगरबी जर्मनी वह देश है जिसकी डिक्शनरी में पाक का मतलब है, पी का मतलब पंजाब, ए का मतलब अफगानिस्तान और के का मतलब काश्मीर —मगरबी जर्मनी काश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा समझता है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी एम्बसीज वहां पर क्या करती हैं, उस बात का वहां पर कोई प्रचार नहीं है। पिछले दिनों हम को मुंह की खानी पड़ी। मैं अपने फौरन मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि वह देश जो खुल्लम-खुल्ला आर्मामेन्टस पाकिस्तान को दे रहा है, हमारा प्रचार का महकमा कुछ भी नहीं कर रहा है। आज पाकिस्तानी मिशन से रोज हमारे पास चिट्ठियां आती हैं लेकिन हमारा प्रचार का महकमा क्या करता है। यह ठीक है कि हम तैयार हैं और हमें तैयार रहना भी चाहिये, यह भी ठीक है कि एक बहुत शान्दार और दानिशमन्द, ज्यूडीशियरी की एक हायस्ट क्रीम, इतना होशियार आदमी आज हमरा फौरन मिनिस्टर है, फिर भी हम प्रपगेंडे में पीछे रहें, यह कुछ समझ में आनेवाली बात नहीं है। प्रोपेंगन्डा डिफैन्स से भी ज्यादा जरूरी है। जब तक वलिन फतह नहीं हुआ था, गोबल्ज लड़ता ही रहा और कहता रहा कि हम ने मास्को फतह कर लिया है। प्रचार बड़ा जरूरी है। घबराने की कोई बात नहीं है, पाकिस्तान को तो हम मुक्कों से पीट देंगे। जब तक हरियाना, पंजाब और यह 50 करोड़ इंसान, गांधी जी के चेले, जब तक भारतवासी मजबूती के साथ अपने कदम जमा कर खड़े हुए हैं तब तक एक पाकिस्तान, एक चीन नहीं सैकड़ों चीन और पाकिस्तान भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं

कि इन पिछले दो सालों में हम और अधिक मजबूत हुए हैं और ऐसा कोई मुगालते में न रहे कि हम कमजोर हैं। हम इन दो सालों में कई गुना मजबूत हो गये हैं लेकिन हमें सदा सावधान व सतर्क रहना है और देश की सुरक्षा को किसी भी तरह की आंच न आने पाये इसका हम इंतजाम करना है। दुश्मनों के प्रति हमें गाफिल नहीं होना है और उनको हमें कमजोर समझ कर आराम से नहीं बैठ जाना है।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री का मशकूर हूं कि उन्होंने पुर अज मालूमात एक अच्छी तकरीर आज हाउस के सामने की है। एक अहम मसले की तरफ सारे हाउस को मुतवाजे किया है। यह बदनसीबी है कि ऐसे मौके पर जब कि हमारे देश के प्रधान मंत्री जनरल अय्यूब को उस ही टोन में जवाब देते हैं जो ताशकंद मुआहिदे की टोन थी उस वक्त हाउस में आज कुछ ऐसी तकरीरें सुनने को मिलीं। श्री प्रकाशवीर शास्त्री को आज की जो तकरीर थी उस में सिर्फ उन्होंने सरकार को सावधान करने की कोशिश की थी कि इस इस तरीके के हथियार उस के पास आ रहे हैं क्या अपना देश इस बात के लिए तैयार है कि वह उस का मुकाबला कर सके? लेकिन उस तकरीर के बाद हमारे कु दोस्तों ने, कुछ मैम्बर साहबान ने हाउस को कुछ इस तरीके से परेशानी में डालने की कोशिश की है कि हम और पाकिस्तान जैसे इस वक्त बरसरे जंग हैं। चीन वाले बिलकुल उस की पुश्त पर हैं, अमरीका उस की पुश्त पर है। रूस भी उन को हथियार दे रहा है और हम बिलकुल अपाहिज हैं। मैं समझता हूं कि हाउस को इस तरीके से परेशान करना और हाउस के जरिये से हिन्द वालों को जो बहादुर हैं और जिन्होंने अपनी बहादुरी का सबूत दिया सन् 1965 में उन को इस तरह से परेशान करना कोई इस देश के हित में नहीं है। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री हमारे जो पहले थे श्री लाल बहादुर शास्त्री उन को लोग समझते थे कि वह बिलकुल एक कमजोर से हैं और कुछ नहीं करेंगे लेकिन जबजंग हुई तो उन्होंने अपनी दिलेरी से सारे देश को अपनी पुश्त पर कर लिया और हिन्दुस्तान की इज्जत और शान को बचाया और बनाया।

मैं यह भी समझता हूं कि इंदिरा जो बावजूद इस बात के कि वह अबला हैं, वह बहादुरी के साथ अपना फर्ज अंजाम देंगी और जो ठोकर पंडित जी ने खाई थी वह ठोकर यह नहीं खायेंगी। इतना परेशान होने की बात नहीं है। आखिर यह मानना ही चाहिए कि सन् 1965 में पाकिस्तान के पास जो हथियार थे वह हम से कहीं ज्यादा सुपीरियर थे लेकिन हमारे बहादुर फौजियों ने अपनी हिम्मत व बहादुरी से उनके वह सुपीरियर हथियार कुंद कर दिये, फेल कर दिये। अब जब पाकिस्तान सियेटो और सैंटो का मैम्बर है तो उसे अरबों रुपये के हथियार फ्री मिलेंगे ही। उस पर हमारा कोई वश नहीं है। अपने डिफैंस के लिए जैसा कि शारदा मुखर्जी साहब ने फरमाया कि हमारे पास इतना रुपया नहीं है कि इन के मुकाबले में ऐसे हथियार खरीदने में उसे लगा सकें। हमारी कपेसीटी उतनी नहीं है कि हम उतना रुपया खर्च कर सकें। वह तो एक मैम्बर है। अमेरीका वारमौंगर है और जहां भी लड़ाई हो, विएटनाम में हो, कहीं भी हो, अमरीका वाले उस का तमाशा देखते रहे, खुद आराम से बैठे रहे और दूसरे लड़ते रहे। जाहिर है कि जब तक अमरीका उन को पुश्त पर है उन को हथियार मिलेंगे। चीन भी उन्हें हथियार देगा ही, मैं मानता हूं कि इन से पाकिस्तान को काफी हथियार मिले हैं और मिलते रहेंगे लेकिन यह मानते हुए भी हम को यह नहीं भूलना चाहिये

[श्री अब्दुल गनी दार]

कि इस वक्त इंदिरा जी की जो पालिसी है इस मामले में वही सही पालिसी है कि वह अपने देश को दुनिया की किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहती लेकिन अगर पाकिस्तान लड़ेगा, कहीं से लड़ाई हम पर थोपी जायगी तो फिर सरदार स्वर्णसिंह की जबान से जो निकला है उस का हम सबूत देंगे। बाकी मैं यह जरूर कहूंगा कि खाली इस तरीके से इस वक्त गरमी पैदा करना देश के हित में नहीं है।

"मनचेमो सरायम व तम्बूराये मनचेमी शरायत"

मैं क्या गा रहा हूं और मेरा तम्बूरा कुछ और गा रहा है। इन्दिरा जी की अपनी एक बात है और सरदार स्वर्ण सिंह की दूसरी ही बात है। इन्दिरा जी और सरदार स्वर्ण सिंह मुतजाद थे। वह एक बोली बोल रही हैं और डिफेंस मिनिस्टर दूसरी बोली बोल रहे हैं। बाकी मैं फिर कहूंगा कि खाली इस तरीके से इस वक्त गरमी पैदा करना देश के हित में नहीं है लड़ाई होगी तो सब मिल कर उसे लड़ेंगे। इसके लिए श्री बलराज मधोक को इतना घबड़ाने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह लड़ाई खाली मधोक साहब ही नहीं लड़ेंगे बल्कि हम सब हिन्दू, मुसलमान मिल कर उस लड़ाई को लड़ेंगे तब जा कर देश की विजय होगी।

شری عبدالغنی ڈار (گوگانوہ) : جناب ڈپٹی اسپیکر - میں شری پرکاش ویر شاستری کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پر از معلومات ایک اچھی تقریر آج ہاوس کے سامنے کی ہے - ایک اہم مسئلے کی طرف سارے ہاوس کو متواضع کیا ہے - یہ بدنصیبی ہے کہ ایسے موقعہ پر جب

کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری جنرل ایوب کو اس ہی ٹون میں جواب دیتے ہیں - جو تاشقند معاہدے کی ٹون تھی اس وقت ہاوس میں آج کچھ ایک ایسی تقریریں سننے کو ملیں - شری پرکاش ویر شاستری کی آج کی جو تقریر تھی اس میں صرف انہوں نے سرکار کو سادھان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس اس طریقے کے ہتھیار اس کے پاس آ رہے ہیں - کیا اپنا دیش اس بات کے لئے تیار ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے - لیکن اس تقریر کے بعد ہمارے کچھ دوستوں نے کچھ ممبر صاحبان نے ہاوس کو کچھ اس طریقے سے پریشانی میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اور پاکستان جیسے اس وقت برسرے جنگ ہیں - چین والے بالکل اس کی پشت پر ہیں - امریکہ اس کی پشت پر ہے - روس بھی ان کو ہتھیار دے رہا ہے اور ہم بالکل اپاہج ہیں - میں سمجھتا ہوں کہ پردھان منتری ہمارے جو پہلے تھے شری لال بہادر شاستری ان کو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بالکل ایک کمزور سے ہیں اور کچھ نہیں کرینگے لیکن جب جنگ ہوئی تو انہوں نے اپنی دلیری سے سارے دیش کو اپنی پشت پر کر لیا اور ہندوستان کی عزت اور شان کو بچایا اور بڑھایا -

میں بھی سمجھتا ہوں کہ اندرا جی باوجود اس بات کے کہ وہ ابلا ہیں - وہ بہادری کے ساتھ اپنا فرض انجام دینگی اور جو ٹھوکر پنڈت جی نے کھائی تھی وہ ٹھوکر وہ نہیں کھائینگی - اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے - آخر یہ ماننا ہی چاہئے کہ سنہ ۱۹۵۶ میں پاکستان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ ہم سے کہیں زیادہ سپیریر تھے لیکن ہمارے بہادر فوجیوں نے اپنی ہمت و بہادری سے ان کے وہ ہتھیار کنڈم کر دئے - قبول کر دئے - اب جب پاکستان سیٹو اور سینٹو کا ممبر ہے تو اسے عربوں روپئے کے ہتھیار فری ملینگے ہی - اس پر ہمارا کوئی دوش نہیں ہے - اپنے ڈیفنس کے لئے یا جیسا کہ شاردا مکر جی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں ایسے ہتھیار خریدنے میں اسے لگا سکیں - ہماری کپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم اتنا روپیہ خرچ کر سکیں - وہ تو ایک ممبر ہے - امریکہ وارمونگر ہے اور جہاں بھی لڑائی ہو ویتنام میں ہو - کہیں بھی ہو - امریکہ والے اس کا تماشہ دیکھتے رہیں خود آرام سے بیٹھے رہیں اور دوسرے لڑتے رہیں - ظاہر ہے کہ جب تک امریکہ ان کی پشت پر ہے ان کو ہتھیار ملینگے - چین بھی انہیں ہتھیار دیگا ہی - میں مانتا ہوں کہ ان سے پاکستان کو کافی ہتھیار ملے ہیں اور ملتے رہینگے لیکن یہ مانتے ہوئے بھی ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہئیے کہ اس وقت اندرا جی کی جو پالیسی ہے اس معاملے میں وہی صحیح پالیسی ہے کہ وہ اپنے دیش کو دنیا کی کسی بھی لڑائی میں شامل نہیں کرنا چاہتیں لیکن اگر پاکستان لڑیگا کہیں سے لڑائی ہم پر تھوپی جائیگی تو پھر سردار سورن سنگھ کی زبان سے جو نکلا ہے اس کا ہم ثبوت دینگے - باقی میں یہ ضرور کہونگا کہ خالی اس طریقے سے اس وقت گرمی پیدا کرنا دیش کے ہت میں نہیں ہے -

"دو ملچھمی سرائم و تمبورائے
من چھمو شراہت - "

میں کیا گا رہا ہوں اور میرا تمبورا کچھ اور گا رہا ہے - اندرا جی کی اپنی ایک بات ہے اور سردار سورن سنگھ کی دوسری ہی بات ہے - اندرا جی اور سردار سورن سنگھ متضاد تھے وہ ایک بولی بول رہی ہیں اور ڈیفنس منسٹر دوسری بولی بول رہے ہیں - باقی میں پھر کہونگا کہ خالی اس طریقے سے اس وقت گرمی پیدا کرنا دیش کے ہت میں نہیں ہے لڑائی ہوگی تو سب مل کر اسے لڑینگے - اس کے لئے شری بلراج مدھوک کو اتنا گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے -

وہ لڑائی خالی مذھوک صاحب ھی نہیں لڑیںگے بلکہ ھم سب ھندو - مسلمان مل کر اس لڑائی کو لڑیںگے تب جا کر دیش کی وجئے ھوگی -]

The Minister of External Affai (Shri M. C. Chagla): Mr. Deputy Speaker, Sir, the subject that we are discussing this evening is the sale of military materials like aircraft, tanks, arms and ammunitions by West Germany to Pakistan. The debate has developed into, if I may say so, a foreign affairs debate and a Defence Ministry debate. In a sense that expresses the sense of apprehension that the House and the country feels at the growing strength of Pakistan arms and armaments.

Before I come to deal with that aspect of the subject, may I put the record straight in view of the remarks made by my hon. friend, Shri Mukerjee. He said that the only assurance we had from the West German Government was that no sale would take place as between government and government. That is not correct. The German Government has given us a solemn assurance that no sale would be made to Pakistan or Iran directly or indirectly, which means that the German Government itself will not enter into any contract of sale of arms nor will it permit any private agency in Germany to enter into such a contract and if such a contract is entered into by a private agency it will not give an export licence.

In the first place we had the assurance of no less a person than the Chancellor of West Germany, Mr. Keisinger. Chancellor Keisinger has told our Ambassador that as far as the German Government was concerned he was fully aware of Indian sensibilities on this question and he would see to it that no arms from the Federal Republic of Germany are allowed to reach Pakistan.

Only a few days back this was what the Germany Cabinet has resolved at its meeting:—

The situation arising from the disclosure in the American Senate Sub-Committee and the representation of the Government of India were fully considered by the Germany Cabinet on the 27th and 28th July and the Cabinet had confirmed the policy of not selling arms to sensitive areas which include India, Pakistan and Iran.

So, we have got now the assurance of the Head of the Government of West Germany and a resolution of the German Cabinet. I submit that in international relations one must accept a solemn assurance given by the Government. As I said, I think here and in the other House, if that assurance is not kept, it is for us to see what next diplomatic step we should take. But so long as there is no evidence about a breach of the assurance or Germany does not intend to keep its pledge and its word, there is no reason why we should doubt the *bona fides* of a friendly country.

My hon. friend, Shri Mukerjee, also said something about the German Democratic Republic. I agree with him that our relations with that country are very friendly. They are growing more friendly. We have a lot of trade and commerce with them. We have taken a step recently which further strengthens the ties between our country and the German Democratic Republic. We have only recently opened a trade centre in that country which I am sure, as I said, will help to increase trade and commerce between our two countries and even further improve our relations.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Why do you not open a Consular Office at least there?

Shri M. C. Chagla: We will consider that. We have taken the step only recently and we will see whether we can do something more to strengthen the relations between our two countries.

Shri D. C. Sharma: There must be a balance.

Shri M. C. Chagla: Coming to the debate as it started, my hon. friend, Shri Prakash Vir Shastri, is not right when he said that we have considered the recent supply of arms to Pakistan as—I am quoting his words—an ordinary and routine supply. We are fully conscious of the fact that Pakistan is shopping all over the world getting arms and armaments. It is not right to say, as my hon. friend, Shri Shastri said, that we are not kept well informed by our embassies and our missions abroad. We have been kept informed; so has been the Defence Ministry. There are military attaches, naval attaches and air attaches in our missions and we get reports from time to time. But these are confidential reports and we are handicapped by this that we cannot disclose these reports to this House or to the public.

19 hrs.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): He wants publicity in papers.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह जो जानकारी मिली थी वह पहले कहां से मिली कि कैनाडा से हो कर जर्मनी को जहाज आये थे ? अपने दूतावास से मिली थी या अमरीका के हमारे सोर्सेज से मिली थी ?

श्री म० क० छागला : जी नहीं, हमें मिली थी। अप्रैल में मिली थी। जब मिली तब हम ने प्रोटेस्ट किया अमरीका में, कनाडा में। पीछे यह साक्षी दी गई, तब मालूम हुआ। ऐसी बात नहीं है कि हमें पहले पता नहीं था, अखबार में पढ़ा तब मालूम हुआ था। हमको मालूम था कि यह बात चल रही है और हमने प्रोटेस्ट किया कि यह नहीं होना चाहिये, और नहीं हुआ।

Now, Sir, I entirely agree with my friend, Shri Prakash Vir Shastri, that it is wrong of the United States, and we have said so in no unmistakable terms, to equate India with Pakistan. The United States should realise the elementary fact that Pakistan and China are in collusion and that Pakistan is a great friend and an ally of China. On the contrary, we are the only country in Asia which can resist Chinese expansionism. I am surprised—I say this with great respect to that friendly country—that the United States does not realise this elementary fact and she goes on equating India with Pakistan. When America resumed arms aid to Pakistan, at that time, we protested and said, "You are starting an arms race between India and Pakistan; you are again equating Pakistan with India. That is not the correct historical perspective which you should take of the relationship between India and Pakistan."

Shri D. C. Sharma: U.S.A. has had more than 100 meetings with Chinese representatives at Warsaw. I think you know it.

Shri M. C. Chagla: I do not think anything has emerged from that. Our reports are that nothing substantial has emerged from that.

I want to remove one misapprehension from the mind of this House, and this is what my friend, Shri Prakash Vir Shastri, said and that is with regard to U.S.S.R. Now, again we have had a solemn assurance from the U.S.S.R., from the highest dignitary in that country to the persons at the lowest levels, that Russia is not supplying and will not supply to Pakistan any lethal weapons.

Shri D. C. Sharma: Ask them to give teeth to the Tashkent Pact.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Let him conclude now.

Shri M. C. Chagla: My friend, Shri Prakash Vir Shastri, said that a lot of Russian arms have reached Pakistan. That is not correct. We are completely satisfied on the evidence before us that Russia has not supplied to Pakistan any lethal weapons. She has supplied other equipment—we cannot object to that—but so far as lethal weapons are concerned, no lethal weapons have been supplied.

Then, my friend, Shri Prakash Vir Shastri, gave a catalogue of arms and armaments that Pakistan has acquired recently. It is a very intimidating list—I agree—but my friend and colleague the Defence Minister, has assured the House, and has assured the country, that we are in a position to meet any Pakistani aggression. It is not possible for him or for me to tell this House what our defence potential is today. My friend, Shri Nath Pai, made fun of our defence and that we have got some museum pieces from the time of 1906. The House should realise and, I think, the hon. Members opposite will realise that it is not possible for the Defence Minister or for me to come and tell you what weapons we have, what armsand armaments we have. Do you want to present this information to Pakistan?

Shri Bal Raj Madhok: We do not want that.

Shri M. C. Chagla: But you must accept the assurance of the Defence Minister.

Shri Bal Raj Madhok: It is the past experience of the last three wars that is creating doubts in the minds of the people.

Shri M. C. Chagla: What is the past experience of 1965?

Shri Bal Raj Madhok: Kashmir invasion in 1947, Kutch invasion and then the last war in 1965.

Shri M. C. Chagla: Let me take the experience of the last war of 1965. What is the experience of this country? Did not the Government defend this country against Pakistani aggression and throw Pakistanis out? Did the Government not rally the whole country behind it and make it resist Pakistan?

श्री रवी राय : अफसोस रह गया कि लाहौर तक नहीं पहुंच पाये ।

श्री म० क० चागला : वह अफसोस होगा, लेकिन सारा देश, और सब कौमें एक होकर पाकिस्तान के साथ लड़ीं ।

श्री रणधीर सिंह : हिन्दुस्तानी फौज सबसे बहादुर है ।

Shri M. C. Chagla: Do not forget that Pakistan had better arms and more sophisticated equipment. But how did we defeat Pakistan? Because the people showed will and determination, the people showed unity, and we had our brave jawans fighting the Pakistanis. I have no doubt that, if there is any future aggression by Pakistan, we will reply to it in the same way as we did in 1965 and with the same result.

श्री ओ० प्र० त्यागी (मुरादाबाद) : अगर चाईना और पाकिस्तान एक साथ आक्रमण करें तब हमारी क्या पोजीशन होगी ?

Mr. Deputy-Speaker: No questions please. Already the scope of the debate has been extended. If the members want replies to all contingencies, there will not be any limit. I will not permit any questions.

Shri Samar Guha (Contai): In the context of the possibility of synchronised Sino-Pakistan threat, the whole discussion will become unreal.....

Mr. Deputy-Speaker: Mr. Guha may please resume his seat. We have already exceeded the time limit.

Shri M. C. Chagla: I am one of those who believe that peace can only be maintained by eternal vigilance. Because we want to be friendly with Pakistan, because we believe in the Tashkent Declaration, it does not mean that we should not be strong. I am again one of those who believe—and I have said so often here and outside—that we should talk to Pakistan only from strength and not from weakness. It does not mean, because we say that we are loyal to the Tashkent Declaration, we are prepared to talk to them, that we should overlook our Defence or should not be sufficiently strong. Pakistan will respond to us better if we are strong and not if we are weak. Therefore, I do believe that any talks that we carry on with Pakistan must be from strength and not from weakness.

My hon. friend Mr. Nath Pai, said that the only solution was a pact between Russia and USA about general disarmament and limitation of supply of arms. He was quite right when he said that both the USA and the USSR have got large quantities of obsolete arms and equipment. Every year the arms development is going on; new researches are made and billions and billions dollars worth of armaments become obsolete, and they want to sell them. That is a great danger to the world. Therefore, unless we can persuade these two mighty powers to agree to a general disarmament or to a limitation of supply of arms, the danger of war will always be there. I entirely agree. This is what India has done about it. I will tell you what India has done in the United Nations. In the Committee which is sitting at Geneva, we have been pressing for general disramament, and President Johnson, after the Israeli war, enunciated five points. One of them was limitation of arms supply and we endorse that. We do realise that, so long as these two mighty powers go on selling arms, the danger of confict, either in one place or in another, will remain. But we have done our best and we are trying to persuade the two mighty powers to agree to something which is sane, which is reasonable, which is statesman-like. I do not think I have much more to say except this that Shrimati Sharda Mukerjee....

Shri Samar Guha: May I submit that....

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. I am not going to permit any questions now.

Shri Samar Guha: He should visit Bonn and Washington and try to convince them of our stand, just as he visited Cairo and Yugoslavia recently in order to convince them.

Shri M. C. Chagla: I am very glad that Shrimati Sharda Mukerjee has sounded the right note. We should not have a feeling of scare or panic. We should not create that atmosphere in our country. Here is our Defence Minister who has assured us that we are prepared, and hon. Members must accept this assurance. I beg of the hon. Members of the Opposition....

Shri Samar Guha: Shri Krishna Menon had also assured us earlier.

Shri M. C. Chagla: ....to accept the assurance given by my hon. friend and distinguished colleague. He knows what he is talking about. As I have said, he is not in a position to give the facts or the details about it. But not only those of us sitting behind but those of my hon. friends sitting in front should accept the assurance given by so responsible a person as the Defence Minister of India when he says that we are prepared to meet Pakistan and we shall be prepared to meet Pakistan if Pakistan chooses to attack us again.

19.11 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 4, 1967/Sravana 13, 1889 (Saka).

GMGIPND—LS II—1775 (Ai) LSD—19-5-68.